SHRI RANGA: You allowed those things to be said...

MR. SPEAKER : I do not know what he wanted to say till he said it. Do you want to prolong it ?

SHRI RANGA : I am not in favour of the suggestion made just now that you call a meeting of the different parties. If you do not allow me to say what I want to, what am I to do ?

MR. SPEAKER : I am not calling a meeting, but I will consult the people concerned.

SHRI S. K. TAPURIAH : You should hear the other side also.

SHRI RANGA : I am not in favour of your calling any conference or any meeting of the leaders of parties. This is not the first time that a split has taken place. When the Socialist Party split, they were recognisod here ; at that time there was no such meeting as is suggested now. Later on, the Communist Party split into two and there was no such meeting. The Speaker exercised his own prerogative and right...(Interruptıon.) This time so m.ny of his friends have broken away frum the main party, and have formed a group...(Interruptions.)

MR.' SPEAKER : I am not allowing any discussion please.

SHRI S. M. BANERJEE Mr. Speaker, Sir......

### 12.50 hrs.

PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL-Contd.
MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mohammad Yunus Saleem on the 18th November, 1969, namely :
"That the Bill to provide for abolition of the Legislative Council of the State of Punjab and for matters supplemental, incidental and consequential thereto, be taken into consideration."

Shri Ishaq Sambhali.

घी इसहाक सम्मली (भमरोटा) : भष्यक्ष महोदय, पंजाब लेजिस्लेटिव कोंसिल को एवालिश करने के लिए जो बिल भाया है में उसकी ताईद करता हूं पोर सबसे पहुले बंगाल के मोज़दा यूनाइटे फन्ट गवंमेंट को इस मीके पर मुआरकबाद देना प्रयना फर्ज समभता हूं कि इस यूनएइटेउ फन्ट ने कर्मिल को एवालिश करने की तरफ एक श्रध्छा क्दम उठाया। चाहिए तो यत़ था कि कार्भेस यह कदम उठाती। लेकिन बदकिसमती यह् है कि कांप्रंस ने तो भ्रभ्रेंों की उन परम्पराम्रों को, उन तरीकों को जो उन्होने श्रपने मकसद के लिए भ्रपर हाउसंज कायम किए थे, उनवो कायम रबा म्रोर पपोजोशन पार्टीज ने, खासतोर पर बंगाल की यूनाघटेए फन्ट गवंमेंट ने उसको एवालिश कग्ने के निण् रन्दनुमाई की हमें खुली है कि उसके बाद वंजाब की पषाली पार्टी ने इसके लिए कदम उठाया प्रोर वह़ां की प्रसेम्बली ने एक राय होकर क यह् रेजोल्यूशन किया। हम तो यह् उम्मीद करते हैं कि प्रब वह वक्ष ज़तव श्रा जाना चाहिए कि इस वालियामेट में ₹ेजोल्यूणन पेश हो घ्रोर गज्य सभा को पवालिका किया जाय ।

प्रьयक्ष महोदय, श्राप जानते हैं कि यह प्रपर हाउसेज भ्रं्रेजों ने घपने मकमद के लिए कायम कित् घे ताकि वह घ्यने मतलत के त्रोगों को इस तरह पर वहां कायम करके प्रवनी मंशा के मुत्ताषिक लेजिस्लेघन वास करा सक्क हस सरकार ने भी उसी चीज को कायम रला। कहां पर तो यह कट्रा गया था कि उसमें बड़ेबढ़ं एक्सपटंस हुमा करेंग, वह भुपर हाउस इसलिए होगा कि भिन्न-भिन्न टाइन के एक्सपटं किसम के लोग उसमें प्रा सक लाईन दद्वाने म यह म्राया कि जो जनरल त्लेषरान म हार गए जिनको पीन्नक न नरंजेंट कर दिया उनको वाकर घ्रमर हाउस म बैठा दिया गया। में पवन ही मूबे की बात कहता हे। हमाँ वद्रा से घ्रभी हाल में राज्य सभा में कोन छुन कर मएए हैं ? श्री मोहनलाल गोनम जिनकां जबिलक

## [ห्री इसहाक सғ्भली]

ने छलीगढ़ में रिजेक्ट कर दिया। जो एलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारे उनको रंज्य सभा में कांग्रेम ने एम्लायमेंट प्रोताहड का दिया । यह् वही मोहनलाल गोतम हैं कि जिनके बारे में इसी हाउस में जोरदार तोर पर कहा गया कि...

घध्यक्ष महोवय : नहीं, तेसी बान न करिए, किसी के परसनल रेफरैंस में कोई बात न कहिए ।

ब्री इसहाक सन्मली यह् इसनिए जरूरी है कि हम छस सरकार को प्रामादा करें कि यह राज्य सभा को गत्म करने के लिए यहां पर बिल लायें। हम यह़ पर इसका पूरा समर्थन करेंगे । श्राज बया वजह है, क्या दुइसारी है गवनमेंड को इसमें ? श्रब तो कांप्रेस वाले यह् कहते हैं कि जो री-ऐक्शनरी लोग ये वह हम में से चले गए। घ्रगर ऐवा है तो सरकार को इसका सबूभदेना चाहिए कि वह राज्य सभा को खत्म करने के लिए यहा पर बिल लाए । ब?किसमती से राज्य सभा श्रोर प्रपर हाउसंज निन लोगों की नुमाइन्दर्गी के लिए कायम किए गए थे, मैं यकीन ग्रोर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि न वहीं ₹ मानसं को लाने के लिए तवज्जह दी गई. न वहां पर एक्सपर्ट्स को लाया गया प्रोर न माइनारिटीज कों मोका दिया गया। वहां सिफं श्रगर कोई चीज थी तो गुटबन्दो का निचदाज करके लोगों को लाया गया। इसनिए् हस बान की जस्रत है. ख्रोर मैं उम्मीद करता हैं तेमे मीक पर जछ कि सरकार की प्रोगेसिव पार्वसीज $T$ निए सारे डेमोक्रेटिक भपोजीशन का सह्योग ऐासिल है ऐसे मोके पर घन री-ऐवशानरीज के निकल जाने के बाद यह सरकार ऐसा बदम उठायेगी घ्रोर राज्य सभा को खत्म करने क fिए यहो पर बिल नाया जायगा।

भालिर में में एक चीज की तरफ घ्रोर तबज्जह निला दूं। जैसा कि मैंने बता $f$ क बगाल की यूनाइटेड फन्ट सरकार काबिले मुबारिकबाद है घोर पंजाब की भकाली सरकार

काबिले तारीफ है, इनके साथ ही मैं भ्रजं फरना चाहता हूं कि प्रोर सूबों में जहां पर कि कार्रेस की सरकारें हैं या काप्रेस पार्टी डन पावर है, उन पर यह क्यों नहीं जोर देते हैं कि वह भी भ्रपने यहां के भ्रपर हाउसेज को एववलिक्ष वर्रे घोर यद्ट जो सफेद हाथी मसूतलिफ मूबों में बंधे हुण हैं ग्रपर हाउसेज की इक्ल में इनको खत्म विया जाय ? में उम्मोद करता हूं, जसा कि कांग्रस की तरफ से दावा होता है वह री-ऐकशानरीज डनकी नरफ से निकल चुके हैं, श्रगर निकल चुके हैं तो यह जहरुी है कि इसका श्रमली सबून दिया जाय, मून्निफ स्बों की कांग्रेस पाधियों को यह् हिदायत की जाय क्र वह श्रपने यहां पर श्रपर हाउसेज़ को खत्म करने के लिए तजबीजें लाएं घ्योर मैं चाहूँगा कि कानून मन्र्री इसके लिए गंीं पर फरमाएं कि वह राज्य सभा, सेंटर कें ग्रपर हाउस को खत्म करने के लिए कब तक तजवीज ला रहे हैं। वह जिस वक्त ऐसी तजवोज लाएंगे, हिमारी पार्टी को ही नहीं, सारे डमोक्रेटिक श्रपोजीशन की मदद उनके साथ होगी। श्रगर मरकार यह कहती है कि प्रतिक्रियावादी, री-ऐक्शानरीज श्रब उधर चले गए है नो सरकार को चाहिए कि मजबूती के साथ तरककी पसंदगी के लिये कदम उठाये, मजबूती के साथ ग्रब पबिलक में किए गत वायदों को पूरा करे। हमस बेहतर मौका उसके लिए क.ब ग्राएगा जब कि पूरे डेमोक्र टिव भ्रपोजीशन की सपोर्ट Еनको हानिल है श्रोर हासिल रहेगी।














اوكيَّ
 ,



 .
 كァ - .
 -....
घ्रध्यक्ष महोबय : ऐनी बात न कfनाr, किसी के परसनन रेफरेंस में कोई बात न कहित्र ।

 براس




 U
 كر كا










< رْ


 .






MR. SPEAKER : Now, Shri Lobo Prachu.
SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : There is just one minute left to one o'clock. So, may I suggest that you may defer it for the afternoon? If you want, I shall start.

MR. SPEAKER : Then, I shall call Shri Prakash Vir Shastri now.

भी प्रकाआवोर गास्र्री (हृतुए़) : मष्यक्ष महोद्य, पंजाब की यह बदषिन्रती है कि प्राज पंजाब कटछंग्र कर बहृत बोटा रह गया है। में भापको पुराने हतिहाम की याद दिलाता हैं । एक समय व? था जब वजाब का नाम पंजाब इसलित गव्वा गया था कि पांच बढ़े दरिया पंजाब में से हो कर निकलते थे। लेकिन विभाजन के वाद जब राबी, भेलन घोर चनाब, तीनों पकिस्तान को चले गए तो चवाभाविक रूप से पंजाब, पंजाब न रह कर दो-माब रह गया । उस पंजाव में से भी हरयाना निकल गया। तो यद प्रोर घ्रोटा हो गदा ऐसी fि्थिनि में मुटी भर लोगों ते लिये एक प्रसेम्बली का कात करे घ्रोर एक कोसिल मी काम करे, यह बात व्यावृारिक नहीं है। हमीलिए 「ंजाब की निग्गन समा मे यदृ निलाय निया है कि वाल के गहन्तु कोसिन को समालन कर दिया जाय प्रोग जनता की मीधी चुनी हुई सम्था ग्रसेंच्बनी ही। बहां काम करे। इसके कित मे पजाय विधान मभा के कायंकतांपों प्रोग मस्व्यों को धन्पबदद देना चाहता हैं। लेकिन साय हो साथ में प्क बान प्रोर
[श्री प्रकाष वीर बास्त्री]
भी कहना चाहैता हैं कि जब पंजाब के घ्दन्दर विधान परिषद् की मव. वित १र हृम विचार कर रहे हैं उम तरह़ के मुठ्ठी-मठ्ठी भर लोगों के उन राज्यों को भी दृम श्रपनी श्रांवों से म्रोंकल नहीं कर सकते जहां ग्राज प्रसेग्ऩलियां काम कर गही हैं म्रोर कोन्सिलें भी काम कर रही हैं ।

MR. SPEAKER : He may continuc after the lunch recess.

### 13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunc/l till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.
[Shri M. B. Rana in the Chair]

## PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL-contd.

भी कंबर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : सभापति जी, मैंने व्वीकर साहब को भी लिखा था कि दिल्ली में बिड़ला काटन मिल में रीत्र एक महीने से कंप्लीट स्ट्राइक है, 6 हज्ञर मजदूर बे कार हैं जिनकी हालत यह हो गई है कि बेचारे भूखों मर रहे हैं । मेरी भावसे प्रार्थना है कि सरकार को पाप कहें कि वह मउदूरों प्रोर मालिकों को मिल करंके कोई रास्ता निकाले। प्राज उन मजदूरों की हालत यह दे कि दिल्ली के नागरिक उनके लिए ध्राटा इकह्ठा कर रहे है, उनकी फेमीलीज भूबों मर रही हैं प्रोग भ्रभी तक पागे कोई काम चला नहीं है। जब तक सरकार इसमें छंट्रेट्ट नहीं लेगी तब तक कुछ होने बाला नही है। इसलिए घ्राप मन्त्री महोदय से कहें कि उन दोनों पक्षों को बुलाकर कोई समभीता करायें इसी प्रकार कोई रास्ता निकल सकता है। दसालए मेगी प्याधसे प्रार्थना है कि ये 6 हजार मादमी जा मूबों मर रहे हैं-यह कोई पोलिटिकल

इड्यु नहीं है इसमें स ी नोग महमन होंगे उन लोगों कर बचने के लित प्राप मःत्री मोदय से कह दें नो बहृत श्रच्छा रह्ये ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's request will be conveyed to the hon. Minister concerned.

श्री प्रकाशवोर जास्त्री : सभापनि जी, दे छ़ में दो राज्य डस प्रकार के हैं जिन्होंने श्रपने यहां त्रिघान परिषऐें ममात्त करने का निइनय किया चे — एक पंजाब श्रोर दूसरा बंगल। यद्यनि इन दोतों राज्यों की विधान सभाश्रों में जांय य संकल्प पारिन हृत उनकं पष्ठर्भूम में उननी गद्धता तो नहीं है जितनी ग्रपेक्षिन थी। क्योंकि विधान सभाश्रों श्रोर विधान पfिषदों की यह परम्पर きे कि जब कोई विधे क विधान सभा से पारिन होना है ग्रो : विधान परिषद की भी स्वीकृति उमे मिल नातो है तब वहु गज्यदाल के पास स्वीक्रनि के चिता भेजा जाता है। 5.1 दोनों गजज्यों में त्रिघान सभा के श्रन्दर जो बहुमत था वही दूसरी पार्टटगों का था श्रोर विधान परिषदों के ग्रन्दग जो बहुमत था वह् दूसरी पार्गी का था। इसनिए उन्होन उस सधर्ष को बचाने के लिए, उन दोनों राज्यों की विधान सभाग्रों ने निइचय किया कि हुमारे राज्यों के श्रंदर विधान परिषदों को समःप्त कर दिया जाय । जैसा मैंने प्राप से कह कि इन विधान परेषदों की समात्ति का निइचय इन दोनों राज्यों की विध।न सभाश्रों ने कोई देशा के हित में किया हो ऐसा तो में नहीं मानता। लेकिन मैं उसका भवशय स्वागत करता हूँ भले हीं उन्होंने किसी निजी कारगा के ध्राषार पर इस प्रकार का निएांय निया हो। परन्तु विधान परिषदें •. केवल इन दोनों राज्यां में ही समाप्त हाँ बत्के देशा क घन्यों र।ज्यों में भी, जहां-जहा विधान पीरषदें है, उन की भी समाधित की जायं देश के ऊपर जो एक भनावइयक ठंगय हो रहा है उससे देषा बच सके । इस प्रकार से में इसका स्वागत करता हैं

मेरा भ्रापसे निवेदन है कि हुमारे देशा में कई राज्य ग्राज भी इस प्रकार के हैं जिनमें विधान परिषदें नहीं हैं ग्रासाम से लेकर परिचम बंगाल तक। पशिचम बंगाल के सम्बन्ध में तो हम निशचय ही ले चुके हैं पासाम से लेकर पशिचम बंगाल तक जिन राज्यों में ध्रब विषान परिषदें नहीं हैं उनकी सूची श्रापके स।मने रखना चाहता हूँ : प्रासाम, गुजरात, हरियागाए केरल, नागालंड उड़ीसा श्रोर राजस्थान ।

एक माननीप सबस्य : घ्रोर महप प्रदेश ।
श्री प्रकाइबोर शासत्री : मध्य प्रदेश विधान सभा परिषद बनाने का निशचय कर चुकी है परन्तु श्रभी विधान परिषद बनी नहीं है। श्रभी बीच में लटक रही है। तो मे इस प्रकार क राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें न होते हुत् भी उन राज्यों के प्रशासन पर या उन राज्वों में किसी प्रकार के स्थायित्व पर विपरीत प्रभात्र पढ़ रहा है, ऐसा में नह़ीं मानता। इसनिए मेरे श्रपने विचाः इस प्रकार के हैं कि जिन राज्यों के श्रन्दर ग्राज विष।न परिषढें हैं श्रोर यह करोड़ों रुपयों का बोभ इस देश के गरीब लोगों के कंधों पर जो पड़ता है उसमे इस देश को बचाया जाये इसके लिए यदि संविष'न में भी संघोधन करने का श्रावहयकता हो तो वह संबोघन भी कर लेना चाहिए। बनाय हसके कि वहां की त्रिधान मभायें प्रह्ताव पारित करके भेजें घ्रोग नब उसके वाद यहां निग्राय लिये जाय। इस प्रस्ताव की उयावहारिकना केवल पंजाब के मम्न्न्र में ही नहीं है बहिक सारे देश के सम्बन्ध में इस प्रकार का निलगंय लिया जाना चाहिए।

दूसरी बान जो मैं विशोष रूप से कहना घाहना हू वह् यह है कि य जो विषान परिपदें हैं घोर साथ में राजग सभा भी है. हनके माहयम से देशा में एक नग प्रकार के अ्रष्टाचार का अन्म हो रहा है। उन विषान पीरषदों के मदस्ग बनने के लिए लोग किस प्रकार से जोढ़-तोढ़ घोर साठगाठठ करते हैं, उस बात को में ववस्तार से नहीं कहना चाहता। लेकिन सम्मवत: पाप

की जानकारी में एक केस भाया होगा कि बिहार के एक व्यक्ति ने राज्य सभा में सदस्य बनने के लिए किस प्रकार से सत्ताएढ़ पार्टी के कुछ सदस्यों को तोड़ा जिस समय :्यायालय के श्रन्दर चुनोती दीं गई घोर न्यायालय ने उन मतों को खोल कर देखा तो पता लगा कि एक पार्टी के लोगों ने श्रवने प्रधि त प्रत्याघी को मत न दे कर के दूसरे प्रत्याशी को मत दिये । उनके पीछे पैसे का बल था प्रोर उसी भाधार पर वे राज्व सभा के सदस्र निर्वाचित़ होकर भाये इस प्रकार की घटनायें, बिहारर, उत्तर प्रदेश प्रोर दूमरे रंज्यों में बराबर बढ़ रही हैं। इसलिए इस प्रकार के जो घ्रपर हाउसेज हैं जिनसे एक नग प्रकार के अष्टाचार को जन्म मिल रहा है उसको गोकने के लिए प्रत्यंत श्रावरयकता है कि विधान परिषदों को समाप्त होना चाहित घोर उसके सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार होना चाहिए ।

पंजाब के सम्बन्ध में मै एक बात घोर कहना चाहता हैं। पंजाब की विधान परिषद कोसमाप्त करने का प्रक्ष हमारे सामने है। पंजाब की घ्रभनी तक माहस घोर बहादुरी की पृष्ठभूमि है 1 पंजाब हमारे देश का सं मावर्ती राज्य है : पंजाब ने सन 1965 में पाकिस्तान के संघषं का सामना न केवल बहादुरी के साथ ही किया बलिक उसने एस देश के ₹वाभिमान की रक्षा भी की। दूसरे शब्दों में ह्म इस प्रकार कहतं हैं कि 1962 के चीनी माकमरा में जो इस देषा का माथा नीचा हुप्रा था उस पाप के प्रक्षालन का कार्य सन 1965 में पंजाब की धरती पर हुमा। लेकिन उसी पंजाब के प्रन्दर प्राज कुष स्वार्थी राज. नितिशों ने म्रवना स्वार्थ हल करन के लि़ पन्य प्रकार के संघर्ष प्रारम्भ कित हैं —新ई किन्दू के नाम पर राज्य चलाना चाह्ता है काई सिख के नाम पर राउ्य चनाना चहाना है प्रोर कोई पंजाबी या किसी धमं विधोष के नाम पर राज्य बनाने का स्वप्न देखता है।

मेरा कहना यह है कि कन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की जाक्तयों दोर प्रवृत्तयों का
[纤ी प्रकाशावोर शास्त्री]
दबाना चाहिये । जो शक्तिया इस प्रकार की हैं कि श्रपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे कन्ने के लिए हिन्दुश्रों श्रोर सिक्वों के बीच में संघर्ष पैदा करना चाहती हैं, श्रोर उन दोनों के कदीमी रिइतों को तोड़ना चाहती हैं इस प्रकार की शक्तियां चाहे पंजाब में हों या बेश में कहीं भी हों. उन को मिल कर दबाना चाहिये श्रोर सब को समान रूप से उस की निन्दा करनी चाहिये ।

दूसरी बात पंजाब क सम्बन्ध में मुभे यहृ कहनी है कि श्रभी कुछ्छ दिन पूर्व वहा पर भाषा का प्रहन उत्पन्न हुग्रा। मेरा ग्रपना प्रिचार है कि जब भाषा के ग्राधार पर पजाब का विभाजन हो गया तो ग्राज पंजाब की भाषा पजाबी है श्रोर यह पंजाब के लोगों को निएगंय करना है कि वह्ट पंजाबी किस तिरि के घ्रंदर लिखी जाये । लेकिन एक बान मैं पजाब की सरकार से श्राप के माध्यम से निवेदनन करना च।हता हूं कि श्राज जब पंजाब के घ्रंदर 45 प्रनिझात लोग इस प्रकार के हैं जो यह् कहते हैं कि हृमारी श्रपनी मातृभाषा $f:$ न्दी है तो पंजान की सरकार को श्रत्पसंख्यकों की भाषा छो संरक्षरा देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी को भानने में किसी प्रकार की कोई प्रापषि नहीं होनी चाहिये । इस से दोनों के सम्न्धों में मधुरता प्रायेगी श्रोर किसी प्रकार के श्रनावशयक श्रान्दोलन से हमारा सीमावर्नी राज्य बचा रहेगा। जहां तक लिपि का सम्बन्ध है, लिपि के सम्बन्ष में मैं बलपूवंक किसी लिदि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हू । मेरा विचार रहा है कि देशा में घ्रवनी लिपियो को सुरक्षित रखते हुए श्मगर प्रादेशिक भाषायें किसी एक सामान्य लिfव को वैफल्पिक लिपि के रूप में सीकार कर लें तो देश की घ्यनेक भाषाप्रों को निकट श्राने में बहुत बड़ी मदद मिल सकेगी। घ्रगर पंजाब के लोग भी इसी प्राधार पर विचार कर सकें तो मैं समभता हैं कि यह पंजाबी भाषा के हित में भौर देष की एकता के हित में होगा।

ग्रन्तिम बान जिम को कह कर मैं श्रपना भाषग़ समा'त करना चाहना हूं वह है प्रशन जो ग्राज पंजाब घ्रोर ह्नग्याग्रा में नन'व का कार बना तुश्रा है, ग्रोर वद्ट है चंडोंगढ़ का प्रइन । सभापतित जों, श्र।प न देखा होगा कि कल इस परन को ले कर गहां एक गर्मा गर्मी का वातावर्रा भी उत्पन्ं हुग्रा। इस के निय मैं मुल्य रूप से केन्द्रीय मरकार को दोषी मानता हैं। सरकार की ग्रपनी प्रादत है $f$ क जो इस प्रकार के विवादासपद प्रइन होते है उन को लमबा टालने की डम की प्रवृति बन गीी है। सरकार सोचती है कि प्रगर कोई प्रश्न लम्बा टाला जायगा तो लोग भूल जायेंगे ग्रोर श्रंत में तनाष ₹नन: ही नहीं रहेग।। इनिद्यास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रशन को ः।रकार ने टालना चाढा नाहे मेमूर्र-मह़ाराष्ट्र का सीपा विवाद का प्रइन हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का भगड़ा हो. चाहे पंजाब के श्रंदर चणडीगढ़ का भगड़ा हो -.. मरकार ने जिस भगड़े को टालना चाहा बह भगड़ा पेर श्रधिक उग्र रूप ले मर के देश के ग्रोर सरकार के सामने श्राया। इसलिए में चाहैंगा कि इस सरका को श्रांगे के लिए यह परम्वरा डालनी चाहिये कि जन भी इस प्रकार के कोई प्रशन श्रायें तो उन प्रइनों पर दृढ़ता से विचार किया जाय प्रोर तत्कान उन का समाधान किया जाय। वर्षों तक उन प्रइनों को लटकते हुए छोड़ कर लोगों को श्रापस में संघर्ष का श्रवसर नहीं देना चाहिये।

चणडीगढ़ के समबन्ष में जब एक निष्षक्ष कमीशन बंठाया गया उस ने तीन बातों को ड्यान में रखते हुए म्रानी राय दी थी। कमीशान का यह निर्गाय था कि चंडीगढ़ हियियागा को दिया जाय, भले ही वह बहुमत से निर्एाय था, लेकिन यह निरांग हीियाग़ा के पक्ष में था । दूसरे जो चण्डीगढ़ की जनसंख्या है उस के प्रंदर किस भाषा के बोलने वाले श्रषिक हैं कमीशान ने उस के श्रांकड़े दिये हैं, उस दृष्टि से भी चण्डीगढ़ का निर्राय हरिपाएा के पक्ष

में जाता है । ग्रोर नीसरे इसलिए कि हीनियाएा पंज।ब के ग्रदर एक fपस्खढ़ा हुप्रा क्षेत्र रहा । श्रब वह श्रगर प्रथक राज्य बन गया तो केन्द्रीय सरकार ग्रोर पंजाब सरकार का दापित्व था कि ह्मारा एक छोटा भाई घ्रगर किसी नरह ग्रपने पिछछ़ेपन को सुघार मंक चंण्डोगढ़ को ले कर के तो ह्टम को इस में ज्यादा रोष नहीं करना चलिंत्र। श्राखिर चंडीगढ़ पजाब को fिले या हरियाग़ा को मिले, रहेगा नो भारन में ही ।

ग्रभी परसों संसद भवन के सामने तीन, चार लाख श्रादमी हरियाणा से चल कर श्राये। क्या लाभ होगा घ्रगर इतने ही श्रादमी पंजाब मे चल कर ग्रायें श्राप श्रंद्राजा लगायें कि य्रदि एंक ग्रादमी के पीछे एक रु० का भी वर्च रखा जाये नो पांच लाख रु० व्यय हनि यगा का हुग्रा। कल को इतना ही हैयय पंजाब वालों का से सकना है। यह जो श्रनावश्यक व्यय प्रोर ग्रान्दोलन की प्रवृत्ति बेश में बराबर बढ़नी चली जा रही है इस को रोकना चाहिये। इन के लिंमे मेर कहना है कि हस के ऊपर तः्काल बिचार कर के इस समस्या का गमाधान करना चहित्रि।

जहां नक पंजाव का गमबन्व है, पहले भी यह प्रशन ग्राया था। कुब्व दिन पहले पैंद्सू की राजधानी पfियाना रहु चुकी भी। यह़ पंजाब एक छोटा सा मुठ्ठी भर लोगो का देश हैं। टिमाचल के केरेकटर करीब करीब वही है जो पंजाब का है। पंजाब ग्रोर हिमाचल को मिला कर एक. राज्य बना दिया जाय घ्रोर fिमले को उस की राजधानी के रूप में परिगत कर (द्या जाय ।

प्रंश्रेजों के जमाने में शिभला उप-गाजधानी थी भोर पंजाव मोर हिमाचल को मिला कर जो नया गाज्य बनाया जाय उस की राजधनी शिमला बनायी जा सकती है इस नरहृ से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि विवादासंद प्रषन को टालना नहीं चाहिये जिस से देड़ा के घंदर प्रनावक्यक

तनाव प्रोर संघर्ष की प्रतृत्ति लोगों में पैदा हो ।

इन ईब्दों के साथ में पंजाब की विषान सभा ने जो विधा; परिषद कों समाल्त करने का निर्यांय किया है उन के उस निर्गाय का स्वा. त कर्ना हू। भले गे गहि नियांय राजनीतिक हृष्टि मे हो। लेकिन if नाह $T$ हू केन्द्रीय सरकान पंजाब प्रोर बंगाल की विधान सभाप्रों के प्रसंनवों को ख्वीकार कर श्रागे प्रपनी ग्रोर से भी ऋदम उठाग ग्रोर संविधन में संशोधन करे श्रोर जिन जिन राज्यों के विषान परिषदं हैं उनको तरकाल समान्त करने को घोषएाए करे।

SHRI REDABRATA BARUA (Kaliabor): Mr. Chairman, Sir, that Punjab has become a smaller State than it was would itself justify the abolition of the upper House in Punjab. But it hardly makes a genuine argument, because a federation is based on equality of Stasus and if a State becomes small, it is up to the federal authorities or those States that are made into a federation to see that all the units are small or at least they are made equal in the Council of States or the Rajyu Sabha. As it is, we have managed somehow to forget this principle. We have allowed the enslavement of small States by the control of the Central Government and the big States. This has unfortunately created this problem. But then I would never accept the argument that being small States they should have no second chamber. The point is, apart from the size of the States, what justification has a second chamber anywhere.

There has been a lot of intellectual debate on this point, and Harold Laski has a lot of spicy things to say about it. He said in his famous book called The Grammar of Politices that even for sovereign States, not to speak of the units of a federation, therẹ can be hardly any justification for a second chamber. There can be hardly any justification because either the second chamber becomes a rubber-stamp, in which case it is noi necessary, or it becomes a challenge to the lower House in which case it violates the democratic principle. It is hardly possible to have a via media in which a second chamber can function wilhout

## [Shri Bedabrata Barua]

thwarting the democratic principle and representative principle and still do something in lagislation that cannot be done without having a second chamber as part of Parliament. Therefore, all the arguments that have been offtred about the second chamber were more or less put at naught or negatived in the beginning of this century, when it was very well stated that so long as we accept democracy, to accept a second chamber is to put a premium on reaction and no amount of sophistication can hide the fact that once you accept democracy and representative principle it would not absolutely do for snybody to suggest that there should be a second chamber to check autocracy of the lower House. As the argument went, there was no such thing, and in India, the constitution-makers never thought of checking the autocracy of the lower House at least in Parliament where there was some sort of check. I have no doubt that that check may begin to operate some day sometime. But where a resolution by the Joint Houses of Parliament, of both Houses and all that, is to be passed, it may become a very dramatic type of experience. But so far as the States are concerned, we have completely made them useless. The upper Houses are completely useless ; they do not have financial powers or large legislative powers : they cannot possibly postpone legislation. There cannot be anything practical.

No reference to the principles of the second chamber was made. They say it was made a job-creating body, just meant to create some jobs for some people at the cost of the State exchequer. It did not sound just as well. I do not believe and I do not agree that those people who are politicians should have no job security. I think politicians also should have some job security or, the politician should be able to devote himself to the country's cause without having the fear of starvation comparatively at a young age of 40 or so.

A politician should be given a job, but the way he is given the job and the way he is maintained should be proper. We should not maintain people who would be useless

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : You want a tea-year term for Lok Sabha?

SHRI BEDABRATA BARUA : No. In some countries it is 3 years and in some countries 4 years. No one has extended it beyond five. However much we may like it, it is not there anywhere in the world.

Even the last speaker who said that the second chamber could have been useful sounded like the 19 th century writers in Britain and France, who used to say about the second chamber that it is not the politicians' world but it is the aristocrats' world. If our princes also wanted some such thing we could have put them there and formed a second chamber, where they could meet once in five years and what they do would not matter at all. But we have not dode it.

The second chamber is without powers. It does not have a semblance of authority. It does not represent anybody. It does not even represent the non-political people. When it docs it does it with is vengeance. When there is a representation for teachers, we introduce a sort of election among professors and vitiate the atmosphere. Whenever the electorate is small. the chances of corruption are greater. It is easier to purchase a small electorate of 30 to 40 people than to corrupt a large-sized electorate. In the United States also, the idea of direct elections came about because they found in a small electorate, the village headman can be easily purchased while thousands of people cannot be casily purchased.

For all these reasons, the sccond chamber should go. In Punjab they have done it nicely. We should try our best to see that every State abolishes the second chamber. It is so useless, functionless and colourless. Without autherity, it becomes less colourful. So far as Rajya Sabha is concerned, it is high time we persuade the entire country to think of a Rajya Sabha which would involve a federal principle. If small States need not exist, Rajya Sabha also need not exist. In America, irrespective of the size of a State, they have two members for each State in the Senate. But in the Rajya Sabha, it is not so. Manipur and U.P. do not have equal number of representatives. Unless we have that equality, in the Rajya Sabha, we do not want the Rajya Sabba also.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Mr. Chairman, the decision to abolish the Legislative Council of Punjab has been related $t$, the ecionomy of Rs. 6 laklis which is spent on it. A little deeper investigation would show that this decision is related to the political disparity between the Assembly and the Council. That disparity occurred in Bengal and the West Bengal Lesislative Council had to go. That disparity has now arisen in Punjab and the Council is going.

The question is whether we should expose our institutions to political manoeuvres of this kind. I would agree with my friends if the second chambers are not paying for what is spent on them, if the second chambers are the fifth wheel. they should be abolished in all States. But if you are abolishing them one by one in the States as and when they become inconvenient to the party in power, you are bringing the Constitution and democracy into contempt. It may be said here that in certain States where the political complexion of the Assembly is different from that of the Council, as in Madras and Kerala

AN HON. MEMBER: There is no Council in Kerala.

SHRI LOBO PRABHU: Yes, you would have abolished it if it werc there. Now the second chamber continues as a matter of sufference. The moment it becomes inconvenient in any State it will have to go. I presume in Madras the second chamber has been properly disciplined about its own existence.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : It is going to be expanded.

SHRI LOBO PRABHU : This is political gerrymandering.

I would not agree with my hon. friend, Shri Barua, that second chambers are unnecessary. He quoted Laski. He was my tutor when I was in England and I have great respect for him. But he seems to have taken a jaundiced view of the second chamber because of the fact that the second chamber he had in mind was the House of Lords which was standing in the way of the House ot Commons. We have to consider the second chamber with reference to article 169 of our Constitution. Our second
chamber is not constituted of princes, as Shri Barua has said. One-third of it is constituted by representatives of local bodies. The question is whethes you want the local bodies to be represented scparately in the legislature. There would be a large volume oi opinion in favour of the view that in a democracy the local bodies should be represented in the legislature. It would not be fair to confuse this repi esentation with the representation of peers in the House of Lords. This is a necessar! representation becausc of the special position occupied by the local bodies in our country.

Then, one-twelfths of the second chamber consists of representatives of graduates I hope no one will object to education being a qualification for election to the second chamber. In fact, it wourd have been very good if we had educa ion as a qualification for election even to this House. If we can get at least some members on the basis of education, representing educated people, I do not think there can be any argument against it.

Then, you have representation for teachers. We have been consistently denigrating the institution of teachers. Is it our intention to deprive them of this little representation? It is true that somebody who is not a teacher may stand for election. Then, you can presciibe by rule that only a serving teacher can stand for election. Similarly, those who represent local bodies must be serving local body men.

SHRI SEZHIYAN : But that is not possible. A teacher cannot stand for election before resigning his past.

SHRI LOBO PRABHU: Then he can come back to the profession. But he must be a serving teacher.

These are representation by election. Then there is representation by nomination. One-Iwelfth of the members would be nominated to represent art, literature, sciencc, co-operation and social service.

Here again, no one will deny that these professions and departments of life are not capable of facing the hurlyburly of an election. You cannot expect an artist or a scientist, who is immersed in his research, to so along and stand for olection. If you want their

## [Shri Lobo Prabhu]

representation and assistance, you must have them by this process.

I would say again that some improvement is possible here. At the moment, what is known as an artist or a scientist is entirely left to the discretion of Government. As far as 1 know Government thinks of artists who are only politicians. I do not want to recall the nominations to the Rajya Sabha last time, but we must have artists nominated by artists. There should be panels for the consideration of Government ; Government should not be free to put politicians as artists into the Rajya Sabha because if they do that, they will not be representing artists but will be representing politicians who have dabbled in art or who know a little of science.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : The Harayana people are very good artists. We do not have any in the Upper House.

AN HON. MEMBER : You are a specimen.

SHRI P. R. THAKUR (Nabadwip) : These people can be consulted without having any representation in the Legislature.

SHRI LOBO PRABHU : You also can be consulted and you need not be here. We will go and consult you in your house. The Legislature is a place where you are by a right.

I will now come to a class to which some objection can be properly taken, namely, the election of one-third of the members by the members of the Legislative Assemblies. To this body the objection properly applies that there is corruption, that unless you pay for a vote the Assembly member generally does not give it to the proper person. Secondly, there is the objection to this class that it follows the party complexion. You are representing the same pattern in the Upper House as in the Lower House. So, if it is possible, we should completely eliminate this third section, namely, that of election by the Assemblies, because it is unnecossary and is capable of being perverted and misused. Ohierwise, I would like to join issue with my bon. friend that the second Chamber is
unnecessary. There is a necessity for a second Chamber.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : This Bill is for abolition of the second Chamber.

SHRI LOBO PRABHU : I will educate you in due course.

There is a justification for a second Chamber firstly, to provide special representation of the kind that I mentioned, secondly, to provide representation for those who would not ordinarily be elected and, thirdly, to provide a brake on the vagaries and extravagances of Lower House. I need not tell you what vagaries and extravagances occur in the Lower House.

SHRI RANDHIR SINGH: We are not extravagant people.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : All the Young Turks come from Rajya Sabha.

SHRI LOBO PRABHU : You are not extravagant.

Unless we get a House which can be steady, sober and studious, 1 think. demucracy cannot function properly, specially in this country. We must have a body which is not reactionary. I think, as my hon. friend here mentioned, Rajya Sabha contributes all the Young Turks, socialism or Communism that exists in our Legislature.

AN HON. MEMBER : Not all; a few of them.

SHRI LOBO PRABHU: Therefore you want a body like this.

Fourthly, there should be deceleration in legislation. You do not want legislation to go so fast that people have no time to examine it properly. The Upper House provides this forum of deceleration to vet legislation which is hastily passed like, fur instance, the Bank Nationalisation Act.

With these remarks about inproving the condition of our second chambers, whether Rajya Sabha or Councils in the States, I would like to support the Bill. I would
like to say that as possible this House should vary seriously consider how to make the second chamber more functional. The people are anxious to get rid of these bodies because they ::re not functional, there is no proper representation and proper authority which only comes from proper representation. Therefore, let us take this opportunity-this is the second abolition of the upper chamber-before there is the third abolition to see whether we cannot make our second chambers mo e functional.

शी प्रोंकार लाल बोहरा (चित्तोड़गढ़) : सभापनि महोदय, हमारे मित्र श्री नोतो प्रभु ने श्रभी जो वक्तक्य दिया है उससे यह भली भांनि स्पए्ट हो जाता है कि वह चाहते हैं कि विधान सभाश्रों में जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर किन्हीं वर्ग विशोषों का प्रातनिधिल्व कायम रहना चाहिये । यह़ बड़ा भारी बुनियादी सवाल है जिस पर मदन को गन्भीरता से विचार करना चाहिए। त्रिधान सभाम्रों में सेंकिड चैम्बर्ज की व्यवस्था क्यों की गई, इसके इतिहास में यदि हम जायें तो हमें घ्रंग्रेजों के जमाने की याद श्रा जाती है। ग्रंग्रेज महाप्रभुश्रों ने ख्वान बह दुगें, नवात बहादुरों, राय बहादुरों श्रोर ऐसे ही कुछ गोगों की शान शोकन को वनाये गखने के लिए ग्रोन उनको राजनीतिक महता प्रदान करने के लिए, उनकी राजनीनिक महत्ता बनाये रखने के लिए, सेकिछ चंम्बज की उयवस्र्रा की थी। ऐसी कोई श्रावइयकता उस ममय नही, यी कि हम जनता के प्रतिनिधियों को चैक बन्नें के निए हस तरह की कोई कगवस्या करें । हाउस श्राफ लाड्ज को श्राप लें, उंग्लैंड भी अननंत्र है । बहां पर च्राउम ग्राफन नार्डंज का निर्माया प्रमीग वर्गो का, वंक्त्रिड दूंटरेस्ट्म कोरी fिप्रिजेटेशन देने के लिए शोग उनका शान जोकन बनाये रबने के लिए, उनोो महनना प्रदान करने के लिए किगा गया था प्रोर वहु चला पा रहा है। उसी च丁न्ट मे प्रंग्रंजों ने घ्रवने क्रिटिश मास्राज्य के गम: मे द्वारे देशे के प्रन्दर इस तरन के संक्रड चैम्बर की व्यवस्था की थी। इनको

बनाये रखने के लिए वकालत करके श्री लोबो प्रभु ने जो सत्य है उसको प्रकट कर दिगा है कि किस तरह से वह घ्राई० सी० एस० वर्ग के जो लोग हैं जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, समाज में गान घोकन से रहने वाले जो वर्ग हैं, उनकी ग्रावाज प्रलग बंग से बलन्द करवाना चाहते हैं। में समभना हूं कि जबकि हमारे यहां जनता की सरकार है, जनतांत्रिक ढंग से तुनी हुई सरकार है, भ्रपने ढंग से हम इसको चलाना चाहते हैं, तो ऐमी ग्रवस्था में में नहीं सपभना है कि जो जनता की प्रात्राज बुलन्द करते हैं, उनकी श्रावाज के ऊपर भी कोई प्रावाज है जो यहां या दूसरे चंग्बर के द्वारा श्रभिउयक्त होनी चाहिए।

हमारे देश में श्राजादी के बाद कहीं भी सिकि चैम्बजं की ठयवस्था नहीं हुई है। राजस्थान में कोई संकिंड चैंस्बर नहीं है। घोर भी कई राज्य हैं जहां कोई संकिक चैम्बर नहीं है। हम एक ही चंम्बर से काम चला रहे हैं प्रोर एक ही चैम्बर होते हुत भी हमें कोई दिककत नहीं हुई है, जनना की घ्यावाज वहा पर बड़ं प्राराम से बुलन्द होनी है, जनसा को सही प्रनिनिघित्व मिलता है। इस वास्ते मैं स 5 भना हूं कि संकिट चैम्बर्ज रख्वना एक प्रनाइयक बान है, एक प्रर्थ हीन बान है, खजाने पर ए₹ प्रकार का बोभ ? हनको समाप्त करके हम जनता के पैसे की जनता के धन की बचत करेंगे ।

प्राप जरा ट्रीट्टवात करें कि मेंक्छ चंमबर्ज में होना क्या है ? वे कात्ते क्या हैं ? iिंकि चंग्बग को ॠोई छस तग़्र का श्रधिकार नहीं ?े. 㤢 जो निचना सदन है उसके ऊप वह कोई नहुन बढ़ा नियंग्रगा गत मंद जो काम निचले सदन मे होना है, उमी कीं पुनरावृति वनो भी होंती है, वही बाम वन्दो भी होता है, वही चर्वासकिक चंश्बर में भी होती है। वहा पर होते कोन लोग हैं ? वहां ंत्रोग होते है जिनका जनना के सुग्व दुम्व के कोई मर्बन्ष नहीं हीता है, कोई सरोकार नहीं होता है। जो
[श्रो ग्रोंकारलाल बोहरा]
जनता की समस्यायें नहीं समभते हैं। वहां लोग ग्रपने ढंग से, श्रपने स्तार्थों का नथा घवने वर्ग के स्वार्थो का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाते हैं - हम श्रवन देश में एक नई ममाजवादी व्यवस्था की स्थापना फरना चाहते है, वर्ग रहित समाज की व्यवस्थ। कग्ना चाहते हैं। उस में मैं नहीं समभात है कि इनकी कोई श्रावष्यकता है। संकंकड चैम्बर की श्राने वाले युग में, समाजवादी समाज की स्थापना के युग में कोई श्रावःयकता नहीं है । सैंकड चैंस्बर निहायन ही प्रर्थहान बेनबुनियाद श्रोर ग्रनावहयक हैं ग्रोर उनको जितनी जल्द्री हो हैमें समाॅ्त कर देना च।हिए।

पईिचम बंगाल ने संकिड चैम्बर को समालन किया या करने का फैस ता किया। पंजाब ने इसके पक्ष में फैसला किया। मैं ममभना हूं कि वहा समय जल्दी ध्राना चाहिए जब हम देश में सब जगह पार्लियामेंट ने द्वारा यह निहचय करें कि संकिड चैंम्बर्ज की हमें कहीं भी ग्राव्वइयकता नहीं है ।

जहां तक केन्द्र में राज्य सभा का सम्बन्ध है, में निवेदन करना चाह्ता है कि हमारे यदा संघ सरकार है श्रोर इसनिए जहां केन्द्र में देशा की जनता के प्रतिनिधित्व की प्रावश्यकता है, वहां देशा के भ्रलग-ग्रलग राज्यों के हित्तों का प्रतिनिधिर्व कर्ने के लिए दूसरे सदन को रखना भी बहुत प्रावपयक है।

में श्रो बरुप्रा की हैस बात से सहमत है कि धू कि हमारे यहां एक संघ सरकार 尹े, इस लिए राज्य मभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के ग्राधार पर होना चाहिए, जसा कि घ्रमरीका घोर श्रन्य देशों में होना है । द्दम लोक सभा के सदक्य तो सीधे जनना से चुनकर श्राते ही है, लेकिन यदि गज्य सभा गे भ? श्रलग-श्रलग राज्यों का प्रतिनिषित्व उनकी जनसंख्या के

अ्राधार पर ही़ाँ है, तो वह न केषल्र एक बड़ी भारी घ्रसंगति होगी बलिक उुटिक्लेशन भी होगा। उदाहरण के लिए श्राप उत्तर प्रदेश श्रोर नागालैंड को ले लीजिय । उन दोनों राज्यों का भ्रपना ग्रवना महत्व है। यद्यजि उन की जनसंख्या में बहुत ग्रन्तर है, लेकिन राज्यों के नाते दोनों की श्रपनी श्रवनी समस्प।यें हैं। यदि र'ज्य सभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के म्राधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो नागलैंड जसं छोटे राज्य कभी भी ग्रपने राज्यीय हितों का सही प्रोर समुचित संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

मैं समभता हूं कि जहां तक केन्द्र का सवाल है. दूसरे सदन को समाप्त करने की दलील बेबुनियाद हैं। देशा के सब राज्यों को प्रतिनिनिवत्व देने के लिए दूसरे सदन ग्रथींत राज्य सभा, को बरकरार रखना बिलकुल उचित श्रोग श्रावर्यक च्च, किन्तु वह प्रतिनिधिं्व समानत के श्राधार पर होना चाहिए, न कि राज्यों की जनसंख्या के ग्राधार पर । में माननीय सदस्य, श्री लोबो प्रभु, को इस बात से सह्मत नहीं हूँ कि राज्य सभा में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहित। श्राज के कानटेक्स्ट, संदर्भ, में वह कतई उचित नहीं है। हां, राज्यों में दूसरे सदन को बनाय रखना श्रर्थहीन है, क्योंकि उनसे राज्यों की भ्रर्थ-ठ्यवस्धा पर एक श्रनावएयक भार पड़ता है म्रोर यह देश की जनता के प्रति श्रन्याय है ।
*SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam) : Mr. Chairman, Sir, the use of four more languages has been allowed in this House. Using that facility I am happy to speak today in my mother tongue, Malayalam.

The Bill that is before the House seeks to abolish the Legislative Council in Punjab. A Resolution has been passed by the Legislative Assembly there abolishing the Legislative Council. This Bill has been brought here by the hon. Law Minister to give legal
*The original speoch was delivered in Malayalam.
force to that. This is a progressive measure and therefore I welcome it.

Why do I say it is a progressive measure? It is said that actually in the Upper Chamber different sections of our society are represented. I am not of the opinion that because of that there should be Upper Chambers in our country. Certain hon. Members who spoke yesterday said that for a thorough consideration of the legislations passed by the Lower House Upper Chambers are needed. I do not agree with that view. Our Assemblies and Parliament du not take decisions which require any reconsideration. Without a thorough examination they do not pass any law. Therefore, Sir, in my oninion these Upper Chambers are not needed. Our Assumblies and Parliament which consist of Members directly elected by our people are responsible for taking the necessary steps with a view to fulfilling the desires and aspirations of our people. Wherever we have such Assemblies and when we have the Lok Sabha here there is no need to have Upper Chambers with power to question the decisions of the lower chambers.

As I said earlier, a resolution has been passed in the Punjab Legislative Assembly abolishing the Legisiative Council there. As far as I know it was prompted to take this ster because West Bengal abolished its Counc:I. There are Legislative Councils in many mire States. They should also be abolished ard necessary steps for that should be taken in the concerned Assemblies.

I was really pained to hear my hon. friend from Madras, belonging to the D.M.K. Party, saying here that they are trying to increase the membership of their Upper Chamber. In this twentieth century when instead of accepting a progressive measure abolishing the Upper Chamber they are trying to increase the membership it cannot be said as a progressive step.

Sir, instead of leaving it to the State Assemblies to decide whether they should have Councils or not and then bringing separate Bills here in respect of each State I would request the hon. Law Minister to bring a Bill amending the Constitution. I am sure he will say that they are in a minority and they may not get the necessary suppott. But I can assure him that if he brings a Bill now he will get the necessary support. Therefore I request him to bring such a Bill immediately.

The hon. Minister may argue that the Rajya Sabha is necessary because whereas in the Lok Sabha there are Members elected directly by the people in Rajva Sabha tho different States are represented. I must tell him that in the Lok Sabha also there are Members from the different States. Therofore a separate House for giving representation to the States is not necessary. If he still says that the Rajya Sabha is necessary I would like to suggest that its constitution should be changed so that the States are given equal representation.

In the end, Sir, I would like to conclude by saying that the Raiya Sabha and Legislative Councils should be abolished and a Bill amending the Constitution on that line should be brought here. With that request to the hon. Minister, on behalf of my Party, I support this Bill.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Sir, while Mr. Abraham was speaking in Malaya:am, they have not taken down the minutes. We got the information from the Lok Sabha office that speeches in Kannada, Malayalam, Tamil and Telugu will be translated into English and Hindi. But we want to n now whether any arrangement has been made to take shorthand notes of speeches in these languages. In that bulletin which we received from the Lok Sabha office, position regarding taking down shorthand notes is not clearly indicated.

MR. CHAIRMAN : There are no short-hand-witers in all these languages here. So ...(Interruptions)

## SOME HON. MEMBERS : Why ?

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : We have given them sufficient notice, Sir. Why should they not arrange for its being taken down?

SHRI RANDHIR SINGH: Somo arrangement mus' be made. We are all one with you.

SHRI A. SREEDHARAN: It should not be done in such a half-hearted fashion.

SHRI RANDHIR SINGH : You may also give your co-operation. Government must give their full $\mathbf{c}$-operation.

MR. CHAIRMAN : But we have taperecording of all speeches.

SHRI E. K. NAYANAR: But the translation in English can be taken.

MR. CHAIRMAN : It will be translat:d from all the languages into Hindi and English.

SHRI E. K. NAYANAR : There aie fourteen languages in which Members are entitled to speak on the Floor of the House.

SHRI RANDHIR SINGH : At least for these four languages, arrangements must be made immediately. We are all one on this.

MR. CHAIRMAN : All the speeches are tape-recorded and they will be transcribed later on. We have no shorthandwriters in all the languages.

SHRI E. K. NAYANAR: We shall get them.

SHRI A. SREEDHARAN: We shall provide them.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members can discuss the matter with the Hon. Speaker.

SHRI A. SREEDHARAN : Tape-record is not the original record. According to the rules, original record must be kept : and tape-record is not dependable; it is not acceptable that way as a record.

SHRI SEZHIYAN: May I make one submission? When Members make speeches in Hindi or Englisi, those specches are being taken down in Hindi or English, as the case may be. Supposing a Member speaks in some other language, then you say that the tape-recording will do. Why should the same method not be followed for speeches in Hindi and English also ? When you allow a certain method for speeches in English and Hindi, the same method can be adoptud for speeches in the other languages also. If the Secretariat feels difficulty in providing stenugraphers, we are ready to provide them.

SHRI RANDHIR SINGH : This matter should be expedited. That is the sense of the

House. It must be conveyed to the Hon. Speaker. The House is one on this that arrangements must be made immediately for this.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): We want a ruling from the Chairman. The Chairman is here and we want his decision.

SHRI A. SREEDHARAN : We want a ruling from the Chair and not from the hon. Member.

SHRI RANDHIR SINGH : I am helping my hon. friends.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : We are thankful to him for his support, but we want the decision from the Chairman.

SHRI RANDHIR SINGH: I think my hon. friends have misunderstood me. I am one with the whole House that arrangement must be made immediately and no delay can be brooked in this.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri A. S. Saigal.

SHRI B. K. DASCHOWDHARY (Cooch-Bihar): I had made a submission that similar arrangements should be made for simultaneous interpretation in other languages also, like Bengali and Assamese, for instance.

MR. CHAIRMAN : That is not before the House:

SHRI B. K. DASCHOWDHARY: I would like to know whether any action has been taken on that matter.

MR. CHAIRMAN : Let him not interrupt the proceedings of the House in this matter. He can see the Hon. Speaker and discuss the matter, and let us see if he is able to help the hon. Member.

AN HON. MEMBER : He must be able to help.

बी प्र०नँस० सहगल (बिलामपुर) : प्रष्यक्ष महोदय, पंजाब कौंसिल के r वालीशन का जो बिल श्राप के सामने है...(ध्यक्षषाग)...

श्रभी श्राप के सामने हमारे मित्र ने भपनी भाषा मलयालम में जो भाषण दिया, में उम्मीद करता हैं कि, हृमें कोई न कोई हम की व्यवस्थ। करनी चाहिए जब श्राप ने ट्रांसलेशन की ठयवस्था की है तो श्राप को थोड़ा सा टाईम इस में देना चाहिए भ्रोर इस के निए भी कोई न कोई व्यवस्धा करनी चानिए ताकि उन को क.) दिंक्रत न हो...

MR. CHAIRMAN : I called upon the hon. Member to speak on the Bill and not on this question.

SHRI A. S. SAIGAL: These things are going on. So, What are we to do ?

MR. CHAIRMAN : I would now allow him to speak on this. If he wants to speak on the Bill, he may do so.

श्री म० सि० सहगल : में इम बिल का समर्थन करने के लित खड़ा हृग्रा हैं । मेरे दोस्त लोबो प्रभु ने यह् बताया :्राप से कि जो बहुन से इन्टेरेष्ट है. जंम कि टीचर्म का है गा प्रोग जो दूसरे लोग हैं उन का रेप्रेजन्टेशन यहां पर नहीं होता है...

SHRI N. SREEKANTAN NAIR : On a point of order.

MR. CHAIRMAN : If the point of order is only for giving information. then I shall not allow it. If the point of order is really a point of order, then I shall hear it....

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: I want your ruling on one matter.

MR. CHAIRMAN : If the point of order proves false, then I shall have to see what can be done.

凶्रो घ्र जस० सहगल : तो में चन रो कह्ना चाहैंगा कि यदि उन को पार्यायमेट : रोग्वा है घ्रोंग गानियामेंट चलेगी तो दोनों ह़ाउसेज, राज्य मभा श्रोग लोक सभा मिल कर के वालंलय।मेंट बनती चे., ऐसी स्थिति में वाप बेषाव यह कह्ठ सकते हैं कि जो पर्fनयामेंट, राज्य-

सभा, में नामिनेटेड मेग्बर भाते हैं उन की संख्या बढ़ा दीजिए, वह भ्राप दस की जगह पछ्बीस कर दीजिए ताकि जो इन्टेरेस्ट दूसगी जगह से प्रा एंगे उन को वह रेप्रेजेन्ट कर सकें। लेकिन यह जस्रो हे क्योंक कि दाज भाप दोखिए नागानैंह में, केरल में, ग्रान्ध में, मष्प पदे:- में, राजस्यान में बौर हर्रयाने में दो चंभ्बर्सं नहीं हैं। इसलिए यह हमारे लिए जनूरी है कि यदि दूसरे प्रान्तों के लोग भाते हैं सामने कि इस को खत्म कर दिया जाय तो बेशक में इस बाते से सहमन हैं कि कित्स नरह से पजाब ने fिया है उसी तरह से हिर एक प्रान्त को कर लेना चाहिए। लेकिन में सहमन डसीलूः नहीं होऊाता कि भ्राप यहां का जं राज्य समा का चैम्बर है उस को लट्म करें। इस के फेवर में में नहं हूं। उस का कारता है कि श्राप के जो दूमरे इन्टेरेष्ट्स हैं उन को रेपेजेन्ट नही करेंगे, प्राप सारे चैम्बसं को खह्म करेंगे तो यहां नामिनेघंस को बढ़ाइए प्रोर नामिनेछांस बढ़ा कर उन को रेप्रेजेन्टेशन दीजिए। नॠ में बेषाक इस मे महमतत है। दूसरे किस्म के लोगों को बराबर यहां पर जगह़ दीजिए।

जिस तरह से हाउस म्वाक लाएंस का यहां पर जिक्र किया, हाउस प्राक नाह्ं म यहां पर नहीं है। हमारे यहां पर लोग चुन कर भ्राते हैं पोर जो लेजिस्लेटिव घमेक्षली वं. भाई हैं बहह हन को चुन कर मेजते है। टाउस माफ लाड्ंस में प्रोर इस में बहुत फकं है। छसर्मल़ मैं निवेदन कहलंगा कि म्राप की जो राज्य-सभा है, हाउस प्राफ लाह्ंस की बराबर कम को कह सकते हैं लेकिन हाउस प्राफ लाह्ंस यही नही है। यहाँ पर हार किसम क लोग प्राते हैं। इसनित् में भ्राप से कहृँग कि जा भा हमारे यहां पर ठपवस्या पह्र हावस्या प्राज कितने दिनों से इस देंा मे बल २हो है, एक बहुत उच्च कोटि की ठपवस्या है पोर इस उपवस्षा को रब कर के हैं प्रोग प्राभ वो चलना है मोर देश को श्रांां ले जानः है। यदि हम सोषालिस्टक प्रोप्राम को कनना चाहते हैं
[श्री श्र० सं० सहगल]
तो हमारे लिए यह सब से बड़ी चीज है कि जो एक चैमचर हो हर त़क जगह पर हर एक प्राश्त में उस के जरित से श्राप श्रमने विवारों को जो भी यहां पर रखे जायें श्रपने सोणलिस्टिक प्रोग्राम के लिए, उस को बराबर उन प्रान्तों में ले जायं। इस में कोई दिक्कत श्राप को ग्राएगी नहीं। हां, जैसा कि मेरे दोस्तों ते बताया कि जहां पर श्राज हमारा राज है या मान लीजिए कि कांग्रेम बंठी हुई है गवनमेंट में उन प्रान्तों में भी उसे खत्र कर देना चाहिए, तो यह वहां उस प्रान्नों के लोगों का तथा विधान सभा का मत ले र के यदि वह खर्म कर देना चाहैं हैं तो बेशक उस को खरम कर दें, हृमें उस में कोई एतराज नहीं होगा ।

जहां तक भाषा के सवाल के बारे में कहा उन्दोंने, मैं कहता हूं कि भाषा के श्राधार पर कुछ प्रांत बने हैं। वहां पर उस भाषा का प्रच्चलित होना प्रवि घ्राइएयक हमें प्रतीन होता है। हां दूसरी लेंग्वेज यदि हिंन्दी को देना चाहने हैं तो दे दीजिए।। लेकिन पंजाबी के श्राधार पर पंजाब बना हुप्रा है तो वहां उन की भाषा पंजाबी, गुर्मु. ?, को बराबर हमें प्रोल्साहृन देना होगा। इस के बाद दूमरी भाषा रखना चाहते हैं तो बेशक ग्राप दिन्द्री श्रोर श्रंग्रेजी रग्र सकते है। लेकिन हुमें प्रान्तीय भाषाप्रों को भी श्रागे ले जाना है। इसलिए यह जहुरी है कि हम प्रान्तीय भाषाम्रों को भी ग्रागे ले जाना चाहतंते हैं तो हमें उन भापरां को चाहे वन नामिन हो, तेलगू हो, कन्नड हो या बंगाली हो, हन सब को बराबर प्रोत्माहन देना चादिए। इन शब्दों के साथ में इसका समथंन करता है।

भी भिख चन्र्र मा (मधुबनो) : स मापति जी, पंजाब लेजिस्लेटिव कौंमिल ए्बालीशन बिल जो हमारे मामने ? हसका मैं तहे दिन से स्वागत करता हूं। पिद्धिले सत्र में बंगाल लेजिस्लेटि₹ कोंसिल कं विधटन का विषेयक घ्राया था

घ्रोर हम लोगों ने उसकी परजोर ताई़द की थी। श्राज उसी रूप में पंजाब लेजिस्लेटिव कोंसिल के विधटन का विधेयक हमारे सामने है श्रोर हम श्राज किर उसका ₹वागत करते हैं । देशा में यहु जो ट्रेन्ड है. यह जो श्रपर हाउसेज को खरम करने का ट्रेन्ड है, यह बहुत ही श्रच्छा ट्रेन्ड है । हर एक जो देश की प्रगति में विष्वास जरता है उसको डसका स्वागत करना चाहिए। यह दूसरा चेम्बर चाहे राज्यों में हो या बे न्द्र के स्तर पर हो, गजज्य सभा के ₹प में यह एक सुपरफ्लुप्रम ची न हो गये हैं, प्क्स्ट्रावेगेंट हो गय हैं । गाजनैतिक पंडितों का कहना है कि यदि मेकेँ चेम्बर लोग्रर चेम्बर की सहमति में है तो सुपग्फ्लुश्रस है, यह्र वह डससे विपरीत है उससे सहमति में नहीं है, तो मिर्चीवस है, खुराफाती है। दोनों तरह से श्रपर चंम्बर का होना जरूरी नहीं है। वह एक सुपरफ्ल़ग्रस बाडी हो गया है। जन हसकी शुरुग्रात हुई भी, जनतंत्र के डतिह्नाम पर प्राप गोर करेंगे तो श्रापको माफ हो जाप्रेगा कि उन दिनों में थोडी बहुत हिस्टागिकल नेसेसिटी धीं। में तफमील में नही जाना चाहता हैं, लेकिन उन दिनों जबकि सैकण्ड चेम्नर की शुरुग्रात हुई थी, उसकी निस्टोरीक्ल नैंमेमटी थी, लेक्रिन ग्राज के मानव उनिच्रास में इसकी दिस्टोरिकल नैसेसिटी नहीं च । डसका व्वात्मा होना चाहिए, चाहे राज्य ₹ं₹ पर हो या रज्य सभा के रूप में हो। लेकिन जब नक ग्राप इसका खत्म नहीं करते हैं, तब तक गजग सभा की जो बनावट है, वह बराबनी ₹ श्राधार पर होनी चाहिये। जिसके मुनालिलक मेगा एक विछेयक विछने सत्र में भी था श्रोर उस पर बहम भी हुद धी।
15.00 hrs .

लेकिन एक बात जो इन्होंने उठाई है ग्रोर जिमको हुप महसूस भी करने हैं कि हमारे देश में जनतंग्र का जो रूभ हमारे सामने है वह डायरेकट केमोक्रसी नहीं है, इन-ठायरेक्ट

डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट छेनोक्रेसी का जो जानदार घ्रादर्शं है，यानी सब त्रोष इकट्ठे हो कर घ्रपनी किसमत का फंसला करें，यह सबसे बड़ा ग्रादर्श है，लेकिन हमारे देश की बड़ी प्राबादी की वज亏 सं यद् सम्भव नढ़ीं है，इसी－ लिये हन－डायरेकट छेमोक्रेसी का रास्ता हम श्रहिनयार कर्ने है। लेक्कन，सभापनि महोदय， श्रापको यह बान माननी होगी लार्जेष्ट पार्टी－ सिपेशन यानी जनता इसमें ज्यादा हाथथ नहीं बटा पाती है। जनतंत्र की गाड़ी को श्रागे चलाने के निये उसमें उनता का ज्यादा से ज्यादरा हाथ हो उसके लिये कोई दूमग रास्ता हैं प्रसितयार कग्ना होगा，जिसमें प्रपर－हाउस न न हो，नेकिन जनता का लार्जे्ट－पार्टीसिपेशन हो। गह कंसे होगा ड डसके लिये हमारे रहनुमा डा० गाम ममोहर् लोहिया ने फोर्य－पिनर स्टेट की बात उठाई थी। डा० लोद्रिया का हहना था कि जनतंत्र में ज्वादा में ज्याद। डायरेकट डेमोक्रेसी को लाने के निय चार－खम्तों का राज्य हो，एक खम्बा केन्द्र है，दूसरा प्रान्त है，तीसरा जिले में श्रोर चोषा गाव में होना चाहिये।
15.01 hrs．
［Mr．Speaker in the Chair］
जिस तरह से ग्राकका यड़ां पर गिप्रेजेन्टेषन है，उमी तरह मे यदि हन चारों जのहीं पर हम नुमाधन्दणी का सिलसिला बना वेते हैं，जनता का भवन हम बना देंते है，जनतंत्र के छोटेटेोटे भवन बना देने है तों उससे जनता का वार्टीसिपे－ जान ज्यादा होगा। इमीलिग उा० लोहिया ने फोरं किभर की बात Еठाई थी। इसमें श्रार－ चेम्बर की जबरतत नहीं रहनी है लकिन साथ ही साथ इस नई प्रगानी से जनता का पार्टो－ सिपेगन ज्वादा होगा，भ्राम जनत। का महयोग ज्याशा प्रालन होगा नथा इममे जनतंत्र का रूप घ्रोर भी ज्यादा स्रूबसूरत ग्रोग वृहद होगा। इसलिंय अभर－चेम्बर वानी दूसरे हाँउस का ब्बाट्मा करना चाहिये तथा कार्थ－दपनर स्टेट की जो भावना है उस पर कानून मंत्री जी को ठो

दिमाग से सो चना चाहिये। गदि प्राप ईमानदारी से देश में समाजवाद लाना चाहते हैं घोर नाहृते हैं कि जनतंत्र भी कायम रहे तो भापको एक न एक दिन इस विचार पर，फोर्थ－पिलर स्टेट पर प्राना होगा। राज्यों में इस समय पंचायतें चन रही हैं，लेकिन उनका क्या रूप है। ये पंचायतें एक खिलोना मात्र बन गई हैं，कुछ लोगों के हाथ में हैं，जो गांवो के दोलतमन्द प्रोर खुशहाल लोग हैं，उन्होंने इन पंचायों कों विलोना बना रखा है，वह रूप प्रच्छा नहीं है। लेकिन इसके मायने यह नहीं होते हैं कि पंचा－ यती राज्य का सिनसिगा चन रहा है वह मिनसिना खत्म हो जाय，हमें उसको भी कायम रखना है। हिन्दुसनान के इनिहाम में यह परम्परा सदियों से चलनी श्रा रही है，लेक्किन जिला स्तर के पैमाने पर श्राज श्राप क्या पाते हैं ？ जिला स्तर पर पंबन्यती राज्य के रूप मे कोई fिस्टम न亏ीं हैं，ग्रफमरों की हुकूपत मे，fिस्ट्रिक्ट मिजिस्ट्रेट म्रोर कलेक्टर की हृक्मत है，प्रफसर－ शाही प्रोर व्यूरोक्रेसी की हुकूमत है जो जनतंत्र का गला घोटते हैं। यहां से भले ही हम प्रावाज उठाते हैं，लेकिन जिना स्तर पर जाकर देखें， कहां तक जनतंत्र श्रागे चलता है，जनता कहां तक दाश्य बटानी है। राज्य के स्र परु तो है－ दिधान मभा है，उसमें नोग माहन्दे बन कर जाते हैं，यहां भी नुम।亏नेते चुनकर भ्राते हैं， लेकिन जिला स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं हैं। इसनिए सारी व्यवस्था को कमिस्टेंट बनाने के लिये कोर्थ पिलर स्टेट बनाई जानी चाहिग，जिस में जनना के सहयोग की ज्यादा से ज्यादा गुं जाहश हो। लेकिन श्रपर चेम्बर की जबरन नहीं होगी， यह मुपरपनुप्रम है，एवं्ट्रेवेगेस है，लीउर कनास की बाडी है，चाहे राउ्य के सतर पर हो या राज्य मभा के रूप में हो। जितनी जल्दी हम एनका खालमम करेंग．दे के के पेसे को बचायेंगे， जनतंत्र को दूषिन होने से बनायंगे मोग भपनी जनन्नत्र की गाढ़ी को प्रागे बढ़ा सर्के।

इन शब्दों के सार्यें है विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हैं प्रेश चाहेँा कि मंत्री
[श्री शिवा चन्द्र भा]
महोदय फोर्ष पिलर स्टेट की भावना पर गम्भीरता से विचार करें ।

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti) : Mr. Speaker, I do not know whether I am speaking from the place where I should be because there have been so many changes, and many members have been worrying about my own personal change-in my appearance.

When we are thinking of this Bill, if at all we are democratic, there should be no opposition to this at all. But we must understand the meaning of democracy, when we are talking such a lot about it in this House In this House, there are a couple of nominated members. In the other House, there are quite a few of them. Does democracy mean election or nomination? That is the issue. If the Upper Houses, wherever they are, are elected, then they are democratically chosen. If they are indirectly elected it is again underdemocratic. Indirect election is not democracy at all. Then let us all be directly elected.

The whole thing is this. We have to make up our mind as to how representative members of the legislatures in the States and here have to be. We hive about 250 million voters here. I have been a member right from the very beginning. Many of my voters do not know where Delhi is

AN HON. MEMBER: Bring them here.

SHRI JAIPHL SINGH: I no not belong to Kanpur.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have not interrupted him. We belong to Balia, Azamgarh.

SHRI JAIPAL SINGH: Balia people are all mad. That was why they got thrashed by the British, and rightly so.

Let us talk a little bit of sense. This poculiar scrt of arguments being trotted out here ralher madden me. What do we mean ? Can you be representative of anybody else but yourself? What does iepresentation mean? Do you represent me?

SHRI S. M. BANERJEE : No.

## SHRI JAIPAL SINGH : You cannot.

## SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I dare not.

SHRI JAIPAL SINGH : He dare not because he has not got the guts to represent me.

What I feel is that it is not a question of the House of Lords. There is one mad fellow from Bilaspur here. He does not know the meaning of the 'House of Lords'.

SHRI E. K. NAYANAR : Is this parliamentary?

SHRI JAIPAL SINGH : We have the 'House of Ladies here, not the House of Lords'.

SHRI S. M. BANERJEE : Tbe lady is a Minister : the lord has no place.

SHRI JAIPAL SINGH: The hon. Member from Kanpur-I should like to be polite to him because he is very much interested in tanneries (Interruptions.) This question of den ocracy is also a question of expense. If I may be forgiven for putting it that way, the whole lot of us here are wasting thousands of rupees in our mad behaviour here. There are people in the galleries who come and see how we work...

MR. SPEAKER : That can be talked among ourselves, not in their presence.

SHRI JAIPAL SINGH : They are much wiser ; they are better observers. They see how we are conducting ourselves. Would you like me to tell you how much it costs our country for us to sit for a day... (Interruptions.) I am not supporting a second chamber as a nominated body, but certainly as an elected body. Somebody said about four houses and five houses. Heaven knows how many houses he wants...(An Hon. Member : Pillars). Why not let everybody have enough? I support this in the sense that if we want to be democratic let us be horiest to ourselves and make representation as representative as possible. It can be possible only if we reduce the minimum of representation and make it as small as
possible. For a country like this, it cannot reduce the number of the electorate. Ours is a large country. For example, I believe the constituency I come from has a stretch of hundreds of miles. I really do not know. They do not know where Delhi is... (Interruptions.) I do not want to be uiakind to hon Members. But I should I like them to be honourable in their behaviour ; I wisu: they were honourable. I have ceased to be dishonourable ; that is why I am an hon. Member.

SHRI S. N. MISRA (Kannauj) : All the aspects of the case have been discussed here. One aspect of the case on which no light was thrown is : consistency. There must be consistency. It is only in the last session we accepted the recommendation of West Bengal Assembly and abolished the Council there. There should be constituency in what we do and without further discussion this Bill should be accepted.

MR. SPEAKER : Shri Sreedharan.
SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : started speaking in Malayaiam.

MR. SPEAKER: You know English very well.

SHRI A SREEDHARAN: But I know Malayalam better.

MR. SPEAKER : Just a minute. There are Members who used to speak Hindi or English very well. This arrangement was just made to help those who do not know to speak in these two languages, I think you will take what I say in the right spirit. If this continues and I have to listen to 14 different languages, God help us. I will just keep dumb uver it. That is all.

SHRI P. P. ESTHOSE (Mavattupuzha) : But, Sir, the interpretation arrangement is excellent. (Interruption).

MR SPEAKER : Order, order. How can one expect everything overnight ? It is geod that we have started something ; but we have not done it cent per cent : we will do it. We are trying to improve it. But you should help me. Those gentlemen who are able to speak and understand English or Hindi, why should they fall into this? I do
not mind ; you can go on speaking, but it is only my request.

धी याबन्त fसहह कुगषाह (भिन्ड) : माननीय प्रध्यक्ष महो़दय, मेरा निवेदन है कि माननीत्र सदन्प भ्रम्रेजो के बजःय यदि घ्रपनी मातृ भ:षा में बोनते हैं नं गह् बहुत श्रष्छी ज्ञात हैं । उसका ट्रामनेशन हो कर हमारे पास श्रा रहा है जो $f$ हमरी समभ में भी श्रा रहा है। कृषया उन को प्रपनी भाष में बोलने दीजिये ।

MR. SPEAKER : We do not know what the country is missing.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Where is the Cabinet ? No Cabinet Minister is there. This is not proper.

SHRI P. P. ESTHOSE : He is a gentleman who knows English also, but he always speaks in Hindi. When Shri Sreedharan speaks in Malayalam, we get through the ear-phones a very excellent English translation.
gHRI SHEO NARAIN : Where is the Cabinet?

MR. SPEAKER : One Minister is sitting. (Interruption)

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Sir, I want to make a brief submission. With due respect to your observations, I would like to point out one thing. There is the question of the record. You were not here when this issue was raised. As far as our speaking in our mother-tongue is concerned, there are two aspects. One, we can better express ourselves in our mother-tongue ; another thing is the sentimental aspect about which you know. You know since our freedom, our Members from the Hindi belt had the privilege of expressing themselves in their mother-tongue, and after two decades, we are getting that privilege. I hope that the Lok Sabha Secretariat would not grudge it and will improve upon the facilities that are already there.

With regard to the records, I have been raising this issue of having a sort of uilingual record in our library as well as those peners which are circulated to Members. What

## [Sluri S. Kandappan]

happens at present is this. Those speeches that are made in English are recorded in English, and those delivered in Hindi are recorded in Hindi. For those who do not understand Hindi, the problem is that we have got to refer to certain things in the library. It is not possible for us to get a translation then and there nor can we seek scme Hindi friends to get it tianslated for us.

I remernber when the DMK group represented by our leader, Shri Anbazhangan met you in the Chamber soon after you were clected to this high office, you promised us that you will look into the matter and see to it that we get a sort of unilingual translation.

Here, I would like to make another submission. Now, the interpretation is coming into effect only in respect of fouc languages. It is very difficult, however efficient the interpreter might be, to have a clear translation. So, I would plead with you that, availing ourselves of the facility that is there for tape-recording, you should see to it that an exact and clear translation of the original speeches delivered, whether they are in Tamil, Malayalam, Telugu or Kannada, is made available to Members cither in English or in Hindi or in both the languages.

MR. SPEAKER: I am very happy that we have made some humble beginning, and I am very hopeful that we would try to extend it and try to get good staff. But for the time being, we are facing a few difficulties. I will call a meeting of the representatives of all the four States and I shall try to understand your difficulties. 1 shall also try to make you understand my own difficulties. But please do not give it a colour. We are all interested in hearing and understanding each other. If we are to speak in our own languages, it is very difficult for the Chair. I will sit here deaf and dumb listening to your speeches. I would be very grateful if those who know English very well can speak in English tull we have some very efficient and competent staff. Every mechanical equipment is available. For the time being, we have acceded to your request and made a beginning.

SHRI SHEO NARAIN: There is no

Cabinet minist:r on the treasury benches. We must have a Cabinet minister.

SHRIS. M BANFRJEE : An ex-Cabinet minister is there by your side.
*SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : Respected Mr. Speaker, I heartily welcome this Bill seeking to abolish the Legislative Council of the State of Punjab. As in several other matters the inspiration for this measure also has come from my State. When I am speaking in Malyalam. I am reminded of 2 lincs by Shri Rabindera Nath Tagore who was a poet of international fame. He had said. "When the heart wishes to pay its debts it must have a coin with a stamp of its own kingdom on it." That, Sir, is the mother tongue.

Sit, the opportunity I have g.t to speak in my mother tongue is as a result of some experimeuts conducted on democracy. It is only another part of the same experiment which prompted the Giovernment to come forward with this measure seeking to abolish the Legislative Counsil of the Punjab. Sir, this Upper Houses have a historical background based on this background we have adopted a method suitable to our country. We have borrowed these Upper Houses from the British Parliamentary system. Basically, there is fundamental difference between our democracy and that of Britain. The Bitish system of democracy was evolved as a result of series of experiments but in India democracy was born out of a national revolution. In the Round Table Conference held in 1931 in London, Mahalma Gandhi, the father of the nation, had explained into detail the role of Upper Houses in the democratic set up of India. He said in the Conference, "Personally 1 am of opinions that we can do with one Chamber only and we can do it to great advantage. We will certainly save a great deal of expenses if we can bring ourselves to believes that we shall do with one Chamber". This was first implemented by abolishing the Upper Chamber in Trivandrum. In the recent past we came across an inspiring experiment in the Indian democratcy. A party which was returned to power on the same symbol, on the sane ballot and on the sume manifesto
has been split into ruling party and the opposition. This was hat-trick of Mr. Nijalingappa. Similarly, when 1 speak of Upper Chambers, two issues come to my mind One is how one can give shape to the representative character. Second is how to share the power in a democracy. Regarding the representative character many eloquent speeches have taken place on the Floor of the House. A progressive democracy accepts only the people's representation. In the Monarchical Britain if there has been an Upper House, it is due to the neculiar situation prevailing there. Upper Houses have been existing as a place for giving berths to those who did not want to get in the Legislature by means of a direct elections In the name of Upper Houses, there has been a lot of political chicanery. Firstly, we have seen instances where people who could not face a direct election getting into the Upper Chamber through its back door. One example I can cite.

In the 1962 General Elections the then Mysore Chief Minister Mr. Nijalingappa was defeated. When he was defeated in the election he put his proxy in the Chair. That proxy had openly said that he was like Bharata who ruled over Ayudhya in the name of Shri Rama. This Mr. Nijalingappa who was defeated in the General Election approched one Mr. Poorna Nand who was elected from Bhagalkut Constituency. He told Mr. Poorna Nand that if he could vacate his seat in the Legislature he could get into Legislature from that Constituency. He made Mr. Poorna Nand resign his seat in the Assembly and was offered a seat in the Council. These Upper Chambers thus give plently of scope for such people to get into the Legislature. Mr. Lobo Prabhu who preceded me said that the Upper Chambers are necessary to give representations to all sections of society such as tcachers, scieritists and eminent technocrats. In my own state there is no Upper Champer, But substantial section of the representatives of the Assembly in my state consists of teachers If you examine the Constitution of any Legislature Assembly. you will come to know that the above argument is hollow. In this Lok Sabha itself the leader of Marxists party Mr. A. K. Gopalan was a teacher himself. In this House there are so many people who have reached the hight of fame in various walks of life.

All of them have come here with the support of the people. India has always respected wisdom and learning. I any one says that in order to give cognition to wisdom and learning we should have soon chambers in this country which has produced Kalidas -nd Profulla Chandra Bose that dis plays only his ignorance or India's cultural heritage.

Today this new experiment is undertaken only at the instance of State Governments. A Rajya Sabha is still heie at the Cenire and these people here do not have the courage to abolish it. Without abolishing the Rajya Sabha, they are now saying : We are bringing forward this progressive measure". We are not fools to believe that statement. In this case, it was Bengal and Punjab which gave a lead and this example which was shown by them will, I home, be followed up by this Government at least at this latest stage. It is only non-Congress Governments like those of Punjab and Bengal which are implementing the ideal which Gandhiji had in mind. The Congress Party which has been in power for the last 22 years has not been abie to abolish Second Chambers.

This measure is indeed a noble measure and as pointed out my honourable friend only a Constitutional Amendmend Bill can bring about a radical reform in our democratic set up and hoping that this will prove to be the first step in that direction, I heartily welcome this measure once again.

## SHRI ABDUL GHANI DAR (Gurgaon) : Spoke in Punjabl.

MR. SPEAKER : Spoke in Punjabi.
MR. SURENDRANATH DWIVEDY: Sir, he belongs to Haryana. Let him speak in Harayanvi.

SHRI ABDUL GHANI DAR : I do not agree with my hon. friend. (Interruption). What is Haryana? What is Uttar Pradesh? This is desh.

पंजाबी ता मैं छमलिए बंला कि पंजाबी भी चोदह् जवानों में मे एक है जो कि कोमी जवान है घ्रोर मेरे मी बाप की जवान है। मुभे इस बात का फस है कि बावजद टंठ पंजाबी हो होने के मैं हमेशा उनकी पीठ लगा कर घ्रता है, हरा कर घ्राता ह्वें घ्रोर उनके यद्रां से घाता है। हन
[श्रो भ्रबदुल गनी डार] जसे न जाने कितने पैदा हा । मैने बड़ों-वड़ों को ठिकाने नाप दिया । मुभे तो हंसी घ्राती है कि:

मु डे कुनड़ों का भुं यारो कट्ठा हो गया हुकूमन का चलाना की ठट्ठा हो ग़ा।

Youngsters have joined hands. Is it a joke to run the Government वह कहते हैं कि दिनेश श्रोर राजा करां भिह के सहाने हुक्षमन को चलायेंगे, कम्यूनिस्टों श्रोर श्रकालियों के सहारे हुकूमत को चलायेंगे ।

श्रो रसाधर ससह : हमें श्रापका पना है
घी घ्रब्दुल गनी उार : श्रापकी माइनानिटी गवर्नमेंट है जो श्राज चल रही है ।

श्री रएणधीर संसह : कन के ग्रादमी, इनको सब पता हो गया ।

भी भ्रब्दुल गर्ं जार : वह् खुद कर्ने हैं कि वह बहुन बड़े श्रादमी हैं ।

भी रताधीर सिह : ग्राप श्रपने मुंहै से कह रहे हैं ।

श्री घब्दुल गनी हार : श्राप जैसे मैंने न जाने कितने देखे हैं ... (ब्यवषान)...

घ्रध्यक्ष महोंबय : मे री समभ में नहीं प्राना $f_{z}$ बैठे-बंठे घ्राप लोगों को न जाने क्या हो जाता है ।

बी घघ्दुल गनी हार : मैं तो भापको मुखातिव कर रहा था।

## पध्यक्ष महोदप : भाप बोलिए।

श्री घब्दुल गनी तार : में सिर्फ श्रापसे यह भर्ज कर रहा था कि घ्राप भी पंजाब में मेक्बर थे घ्रोर में भी मेम्बर था जब इसका जन्म हप्रा। उस वक्त मैजोरिटी ने मुख्य मन्त्री को लिखकर दिया था कि हस हाउस की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बक्त खयाल यह्ह था कि

सैंटर किसी तरन्न गे कमजोर न हो। सैंचर की नाकन में fिकी नउज्ञ की न ग्राये । यह भी रुयाल था कि उस पर चंक गच्न चाहिंत। वहां पर गवर्नर की तरफ से दूमरी तरफ मे भी कुछ गेक होनी चाहित । इम नरह से श्रमम्बनी श्रगर कोई गलनी भी करे तो वह उम गलनी को दुरुम्न कर मकेंगे ।

लेकिन उस व₹त पजाब बहुन बड़ा था। हीरयागा भी उसमें प्रा ग्रोर निमाचन प्रदेश का बहुन बड़ा निस्मा, f九सको कागड़ा कहते हैं, वह भी उसमें था। इसलिए खर्च को हानन में न रखते हुए, बड़े मकसद को ड्यान में रखते हुए ग्रानियद कि मेंटर मजबून रह, ह्मने इस बात को माना श्रा 尹्रोर् श्रापने भी स्वोकार कर लिया या। ग्राप वहां स्पीकर भी रह चुके हैं प्रोर मिनिस्टर भी रत्रे चुके है। ग्राज पजान्न ने, जहां श्रकालियों को हुकूमत है यह कदम उठाया है । मैं श्रकालियों ग्रौर कम्यूनिस्टों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हैन गह् कदम उठाया है । घ्रोर उठाकर सग्कार को खुद मौका दिगा ₹ंग्ने का कि त्रानज़ूद इसकं हम अ्रक्मारयन में है हम इतनी बड़ो चीज ला सकते हैं।

भो रएाधोर सिह : जनसघ को क्यों नहीं कह்ंते ?

श्रो ग्रब्युल गनो डार : लकिन बावजूद छसके वह मैजोरिटी में है, इस खयाल से कि देश का दिति इसमें है प्रीर खामर्वाह रुपया बरबाद न हो, रिपिटीशन न हो उन्दोंने कहा कि इस हाउस की जहृरत नहीं। में उन्हें बधाई दता हुँ, मैं सरकार को भी बधाई देता है कि उसने जो मुतफिका राय थी उमको लव वयक कहा !

लेक्रिन घ्रापकी गैर-हाजिरी में मेरे भाई घमरसिंत्ह सहुगल ने, वह मुभे बह्रुत प्यारे है, कहा कि राञ्य मभा ग्हनी चाहित । श्रो लोवो प्रभु ने भी यह खयाल दिया कि कौसिलों में

लोक्ल वाडीज पंच्रायतों श्रोर एजुकेशानिक्ट्स वगँग्रु की नमाठन्द्नगी की जरूरत है। जो नामजद होते हैं उनमें श्राटिस्ट्स भी होने हैं， साडंटिस्ट्स होते है．，सोशल सीवस वाले भी होते हैं। जो लोगों की ग्जिदमत करने हैं，उनको लिया जाना है। दूस वक्त श्री सहगल ने बहुन घ्रच्छी बतं कही कि राज्य सभा में नामि－ ने ठन बढ़ा दिया जाये तारक डन लोगं। की काफी नूमाइन्दगी भी हो जाये । मैं उन पर कु－निन जक कितनी सादगी से नामिनेशान को बढ़ा लेना चाहते हैं नाकि गज्य सभा को बिलकल खिलोना बना दिया जां ग्रोर प्रधान म₹न्री जिसको चाह्ं उसको उसमें ले ग्रायें ।

बहग्हाल मुभे उसको खिलोना बनाने की तकन्रीफ नही है क्योकि 心नकी जो घ्रवमारयन थी । घ्रब वन्र ग्रक्लयत में बदल गई है झ्रोर कल यद घविलगत शायद टधर तहारीफ ले श्राये। भ्रगर कम्यूनिस्ट भी उनके माथ इधर ग्रा जायें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं दे क्योंकि कम्यूनिस्ट समभ，दार हैं। वह पहले साथ देते हैं घ्रोर साथ देकर उसंक्राद गिगते हैं，जैसे उन्होंने बंगाल में कंका। बंगान की ममस्या को श्री रणधीर सिद समभ सकते हैं। मेरे भाई बहुन काविल एडवोकेट हैं，वह् समक सकते $\begin{gathered}\text { त } \\ \text { कि कम्यूनिस्ट }\end{gathered}$ किस तरह नाकत में प्रायंय श्रोर बह माप्रो ₹से तुंग या चाऊ एन लाई न हो कर मी किस तरह से राज्य कर रहे हैं ；में उनको समभाना चहता हूं कि पहले उन्होंन नोगों के दिलों पर राज्य किया，लोगों को श्रपने साथ मिला लिया। क्यों मिला लिया ？कयोंकि ：

मुं डे कुं尹्यों का भुंत्र यारो कट्ठा हो गया हुकूमत का चलान की ठट्ठा हो गया।

यह यंग्स्टर्स कहते हैं कि नुड्ढों को मार दो，बुड्ढों की जहुग्न नहीं है। उनको समभ में श्राना चाहिए कि बुछ्ठों को मी होना चाहिए।

## जहां बानी से है

दुश्वार तरकारे बहो बीनी，

जिगरखूं हो नो च巨मे दिल में
त्रोती है नजर पंदा ।
हकूमन चलाना कोंई एमान बःत नहीं है ग्राज जो लोग यही पर हैं उनको मोचना चाहिए कि जनँ कम्यूनिस्टों नं：सगकानें हैं बन ही मपर काउस उड़ाये जायंग। ग्रापको एक ． दिन प्रमेंड्डमेंट लाना होगा ख्रार कांस्टिट्यूपान को बदलना होगा यह् कहा जः गगा कि राजय मभा की कोई जरूगन नहीं हैं श्राइन ग्रपना है । ग्राइन हमने बनाया है। गः कोई मजहवो किताब नही गै वेद मुकद्दे नहीं है，गुरु प्रन्थ नड़ी है．इजील मुन्बए नहों है। यह हमारा बनः या हुग्रा ग्राईन है ।

ग्रगर हैम ईमानदारी से रोचें तो राज्य सभा कोई कास्टट्यूरान नंओ कर सकी है， कोई नई बात नहीं कर सकी है，नई बात नहीं ला सकी है，इम्प्रव नही कर सकी है，हमारी नालायक्रों पर पऱा डाल सकों है तो हमे समभा नही，सकी है। हकीगन में जब जो सम।ज़ादी लाग है चे उधर बैठग दो वे श्रपर हाउस गो नही रहुन दंगे। श्र्री घ्रमरामें；सहीय की बात नही चलेगी। र।ज्य मभा जरूर जायेगी प्रोर इसका वह् मान ल । घयよ वह नहा मानत हैं तो ग्रब भी वक्त है fक्ष उनक। मान लना चाहिए।

करीब है यारां राज महषार ध्दवगा कुछता का घून क्या कर जां चुप रंहगी जवान खजर
नहू पुकारेगा प्रास्तीन का।


 اورانک尼


Youngsters have joined hanc＇s．Is it a joke to run the Government？




 تخرى


－ك

ارهِّتْ




夕



 حبرطرب ，

 ，



 كركّ برمةず

نيّى أبك


 －隺

 ．

 أنهيت يِ يملزَ




 كی（ ，

نـُ




$$
\begin{aligned}
& \text { بَرْ }
\end{aligned}
$$

 كوجنا 1，

 （奖







$$
\begin{aligned}
& \text {; ; } \\
& \text { T }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (6. } 6
\end{aligned}
$$

SHRI J. N. HAZARIKA (Dibrugarh): I rise to support the Bill because the people of Punjab want the abolition of the Legislative Council. The abolition or continuation of any Legislative Council is the concern of the State itself and it does not concern the entire country. The people of Punjab want that it should be abolished. Therefore, I support it.

There are a lot of arguments for and against the existence of the Second Chamber. One of the reasons on which the existence of the Second Chamber is justified is the theory of checks and balances. All students of history and politics know that there are both the sides for the existence of the Second Chamber. It is necessary sometimes even at the cost of democracy also because it gives an opportunity to the Government to review a matter passed by a democratic legislature. Everything done in democratic legislature may not always be correct and perfect. Therefore, a second thought is necessary for which the Second Chamber is provided. One of my hon friends has said that the Second Chamber provides rehabilitation for the defeated candidates. Actually that is not so though it is being utilised not only in one case which was referred to by one of my hon. friends-Mr. Mohanlal Gautam--but also in two or three more cases, namely, Mr. Ajit Prasad Jain and Mr. Malaviya who were defeated in the elections, were taken in the Rajya Sabha. I am not very much concerned how people go there and all that. In the past in our country the Second Chamber was necessary to give representation to those who were unrepresented in the democratic legislature ; certain people could not be represented in the elected legislatuie and they could be well accommodated in the Second Chamber. As some of my hon. friends have said, sometimes persons who really have to be represented in the democratic legislature in the interest of the country who are not other wise represented, have to be accommodated in the other Chambers so that the country may get the
benefit out of their representation. So, in o ir Central Legislature here, we have got two Chambers. But, on one point I cannot agree. G vernment may have a legisla*ion or may have the Constitution amended so that any community or any section of the country whose representatives are nominated by the President now, need not necessarily be represented in the democratic legislature of the Lok Sabha. If they are not elected in future, they should be represented in the Rajya Sabha because their presence sometimes disturbs the balance of the House at the time of Division in the Democratic House. Therefore, in our country in the Lok Sabha when there are representatives who are nominatel, they should go and they should be given representation in the Rajya Sabha.

I do not agree with mv friend, Shri Bedabrata Barua who spoke earlier that the size of the State does not matter for having a second Chamber. It alwavs matters from the point of view of viability of that particular State. One of the viabilities is finance. Therefore, the size of the State is alway counted. It is not always based on principles. Sometimes on some principles one can justify a second Chamber and on the ground of practicability also. Therefore, it depends upon the people in a particular State whether they would lihe to have the Legislative Council continue or not and if they want it, we should supp.rt it.
With these few words I support the Bill

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM) : Mr. Speaker Sir, I am grateful to you for giving me a chance to say a few words in reply to the points raised by different hon. Members. I am really very much grateful to all the hon. Members who have unanimously supported this Bili. There was not a single Member who oppose it. Therefore, I am very grateful to all of them.

But a few proposals have been placed before this House for considuration. All the Members have unanimously expressed their view that they are in favour of the abolition of the Legislative Councils from the States. But it is with in the purview of the State legislation. There are only
[Shri S. M. Yunus]
somi States which have been excluded and where there are no Legislative Councils. But in all the other States there are Legislative Councils by virtue of the amendment introduced in the Constitution from time to time. Now, if the States are coming forward with proposals that their Legislative Councils may be abolished, we are considering their recommendations and wherever such a resolution passed by the Legislative Assembly of that particular State as provided in Article 169 of the Constitution is received by us, we waste no time in taking active action and the Bill is prepared and introduced for consideration of the House. So, wherever there is any proposal to that effect, it shall receive the consideration of the Government.

One hon. Member from Tamil Nadu belonging to DMK expressed a grievance that the State of Tamil Nadu has sent a resolution of the Assembly recommending an increase in the number of members of the Legislative Council.

A similar Resolution or Proposal was also received by the Government from the Maharashtra State and both these proposals were considered by the Cabinet and they are still under conside:ation and some suitable action will be taken very soon

Therefore, so far as that question is concerned, there is nothing to worry.

Now, as regards the question of the abolition of the Rajya Sabha, some hon. Members have expressed the view that the institution of Rajya Sabha is not necessary, it is an unnecessary Chamber and that it should be abolished.

Sir, the question of abolition of the Rajya Sabha is not as simple as that of the legislative council of the State. Whereas the legislative council could be abolished simply on the basis of a Resolution passed by the Assembly of that particular State, this is not the case with respect to the Rajya Sabha. For Rajya Sabha, amendment to Article 80 of the Constitution has got to be considered I can assure hon Members that this suggestion will also receive consideration from the Government when properly placed for this purpose.

There is nothing more to be replied to and I once again thank the hon Members who have given support to this Bill.

MR. SPEAKER : I think all of us should adopt the Bill rather than taking more time. Actually we have taken thrice as much time as was scheduled for it.

The question is :
"That the Bill to provide for the abolition of the Legislative Council of the State of Punjab and for matters supplemental, incidental and consequential thercto, be taken into censideration."

The motion was adopted.
MR. SPEAKER : The question is :
"That clause 2 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clauser 3 to 9 were added to the Bill.

MR. SPEAKER : Now, the question is :
"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1 , the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. YUNUS SALEEM : Sir, I move :
"That the Bill be passed."
MR. SPEAKER : Motion moved :
"That the Bill be passed."
SHRI S. N. MISRA (Kanauj) : There is one constitutional difficulty that you have. Article 168 provides that for every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor ; and in the State of Punjab, two Houses. Article 169(2) provides that any law referred to in sub-clause (1) shall contain such provision for the amendment of the Constitution, as may be necessary to give effect to the provision of the law. Therefore, I suggest, from Article 168 (a) the word 'Punjab' should be deleted.

MR. SPEAKER : I am told, all these difficulties were gone into and they are quite aware of it.

भी भीचन्व गोमल (चण्डीगढ़) : प्रष्यक्ष महोदय, जिस विधान परिषद् को समात्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया है, मैं स्वयं दो बार उस का सदस्य ग्हा हूं। मुभे यह भी म।लूम है कि. उस सदन का कान्ट्रोब्यूशन मगएचनीय रहा है, परन्तु सिद्धान्न रूप में में इस निष्कषं पर पहुंचा हैं कि म्राज जितना धन हम को उस दमरे मदन को कायम रवने के लिए ठगय करना पड़ता है. वह ग्राज नमारा देश उठा मकने में ग्रमपर्थं ग्रोर उस व्वयक की नूलना में दूमरे सःन की उपयोगिना नह़ीं के बराबर? जन श्र्रंजेजों के जमानों में बाईके मरल लेजिमलचर दोहरे विषान मंडल, की प्रथा चलो थी, तो उम समय गायद उद्दे इय
 कर्रा चै, नो ऊपर चाना मदन उस की दुरस्नी कर मके मैं न मान प्राठ गान न不 पंजाब की त्रिधान परिषद् का कार्य देखा हैं। उस काल में रायद दो तीन ऐमे प्रसंग श्राये होंगे, जन्र उस मे कुल त्विधेयकं पर संगोधन उाद्धन कियंय गमं जो कि बाद में विशान मभा को स्वरकार करनें पडें।

दून गरे मदनों की स्थापना के पीछे तक उद्देंड्य गद था कि जो व्यनिन विज्ञान, कला, समाज-मेवा के क्षेत्र में विरोष स्यान रखते हैं या किमी म्यन्व विषय के विरोप ज्र हैं, हूं कि चुनाव के द्वारा उन्हैं खह़ां पहुंचने का श्रवसर नहीं मिलना है, उसनिए उन्हें दूपरे सदन में स्थान दे कर उन की गोग्यता से लाभ उठाया जावे। परन्तु विछ्घले दम बागद्र वर्वों का अनुभव बताता है कि उस भावना को ममाप्त कर के राजनितिक उड्ंदगों से प्रद्न क वर्यक्नयों को सदन का सबस्य बनाया गया।
15.56 hrs.

## [Shri M. B. Rana in ihe Chair]

जो ठयद्वन च्चनाव में हार जाने है, या जो क्रिंति गजनेंति टन के नित् व्रनेक प्रकार से

कष्ट का कारण बन जाते हैं, उन को एकामोडेट करने के लिए दूसरे सदनों का उपयोग किया गया।

इस स्थिति में प्राज दूसरे सदनों का बिल्कुल कोई ध्रोचिं्य नहीं रन जाता है। वेस्ट बंगाल घ्रोर पंजाब की स क्कारों ने श्रपने यहां दूसरे सदनों को समाप्त करने का नेक कदम उठाया है। इस निए वे दोनों चधाई की पा त्र हैं। ग्राजा है कि दूमरे राज्य भी उन से प्रेराा लेंगे ग्रोर दूमरे सदनों के निर्माण से जनता पर जो भारी भरकम चवच का बोभ, पड़ता है, उस को दूर करने का प्रत्त्न करेंगे ।

प्राज जिस ढग से दूसरे सदनों में सदस्य डाल दिंग जाते है, यदि उसके स्यान पर विभिन्न वयदसायों, वकीनों, उाकटर्ंों प्रोर लेबर के क्षंत्र में काम *न्ने वालों ग्रोग ग्रन्य विषोषझों को इन दूसरे सदनों में प्रतिनिधिं्व दिया जाये म्रोर उस के घ्रनुसान भ्रलग घ्रलग हलंक्ट्रल कालेज बनाये जायें, गे मैं समभता हू कि इस देंश में दूमरे सदनों की कुच्ठ उपयोंगितः हा सकती है। या तो सारे देक्र मेंदूनरे मदर्नों को समाप्त कर दिया जांग भ्रोर या उन के वरंमान ढांचे में परिवर्तन किया जां, तांकि उन की कुब्ध उवयोगिता हो। कम से कम श्राज उन की उपयोगिता बहुत कम रदे गई है। वर्चें ז प्रनुवान में तो उन की उपयोगिता बित्रुल नहीं है। हस लिए में इस विषेयक का समभंन करता है।

[^0][^1][Shri E. K. Nayanar]
of that effect we are now passing this Bill abolishing the Legislative Council in Punjab.

Sir, the atmosphere in our Country has changed after the 1967 General Elections and because of that we find these changes being brought about. Instead of abolishing the Council in each State and bringing a Bill here it would be better if a Bill amending the Constitution is brought here enabling us to pass a legislation abolishing all Upper Chambers.

There are some people and some interests who want to retain the Upper Chambers. Why is it that this matter is proceeding very slowly. In 1956 when the reorganisption of States took place on the basis of language there was very strong objection from the ruling party. But ignoring that opposition the reorganisation of Andhra, Maharashtra and Maha Gujarat took place. After the General Elections of 1967 it has become casier to make these changes. In many States the Congress has lost power. The States which have decided to abolish Legislative Councils are not those where the Congress is in power. These changes can be brought about if a Bill amending the Constitution is passed by us and then we will be able to carry out the desires and aspirations of our pcople.

Today we have two Chambers at the Centre. The Upper Chamber is not necessary. Crores of rupees are wasted for the purpose of maintaining this Upper Chamber. The Lok Sabha has got more powers to bring forward legislations. I am not saying that the Upper Chamber should be abolished altogether: I am only saying that its constitution should be changed so that all nationalities are given uqual representation. The problems of minorities should be attended to and removed. For that pu pose their representatives should discuss with equal powers. In a vast country like ours there are many minority problems and communal problems. They should be given proper representation and for that an Upper Chamber is necessary with equal powers as the Lok Sabha. Hy mere abolition of Rajva Sabha it will not help the progiess of democracy.

As a beginning. Sir, the Punjab Legislative Council is being abolished, under Article 169. I think, there are nine

Legislative Councils. In two States they have been removed. Even though there is a proposal to abolish the Legislative Council in Madhya Pradish, no legislation has yet been framed. All Upper Chambers should be abolished and Rajya Sabha also should be abolished. Instead of Rajya Sabha in the Lok Subha there should be representation of all nationalities and in that way we can solve the problems of minorities. With this suggestion, Sir, I welcome this Bill.

### 16.00 hrs.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): I would not normally have stood up to participate in the third reading on a Bill like this because the final decision on a matter like this belongs to the State Government which has chosen in its wisdom to abolish its Upper Chamber but 1 am taking this chance to express a thought or two because some hon. Members have taken an extreme point of view and have said some harsh words against the second chamber in the States as well as the Rajya Sabha here. I do not want to go into the entire history of the bicameral structure of the legislatures. This will have to be left to the best judge ment of the assemblies concerned. But I submit with humility that democratic institutions have not yet taken such a crystallized shape and our traditions are still young and a lot is said on what is freedom and democracy in this country and new definitions flow from new leaders everyday.

Therefore, if we have a second House, it means just second thoughts for any item of programme or legislation that we have. I have not stood up here to say anything against the Bill, which I made very clear. I would like to say, before I s:t down, that it shouid have an early passage. But, as I said, it is not fair at this stage of time in which our country is situated, to take an extremely harsh view and say that the second chamber is completely either out of tune or completely unnecessary.

Mention was being made that the second chambers are not at all representative of the aspirations or the needs of the people, just because they are either nominated or just because their entry in that House is based on indirect elections. I would only like to say that unfortunately,
to a very large number of people, elections to the Lok Sabha and also to the Assemblies have become very expensive both in terms of time and in terms of money. There are a very large number of people who cannot afford it: some people do not have the inclination: others do not have the resources ; and then there are special categories as pointed out by some Members, like artists, scientists or philosophers or research people or even students and minorities who would have to be nominated in one time or another in our present system and in our way of life for quite sometime to come. Therefore. I would like to counsel that each perticular action like that would have to be careful, that we should hasten slowly as far as these things are concerned.

With these few words. I would like to commend the passage of this Bill.

श्री अगेइवर यादव (बांदा): श्रक्यक्ष महोदय, पंजाब विधान परिषद् को भंग करने के विषग्र में जो यद विल ग्रा $\Gamma$ है में उस का हादिक स्प से ममर्थन करता हूं श्रोर बंगाल मरकार ने भी जो यन्ं की विधान परिपदों को भंग करने की ध्रगुताई की है उम के लिए भी में घन्ग्रवाद देता शें। मै चान्ना है कि प्रान्तों की हग्एक विधान परिषद़ को ग्वत्म कर दिगा जाय श्रोर इम से जो वैसा बचे वह पिद्र्रे डलंकों के उतथान में लगाया जाय। मैं गद भी चाहता हूं कि केन्द्र में जो राज्य सभा है उम को भी भंग किय्रा जाना चानित्। 5 सको भंग करने से घ्रोर विधान परिबदों को भंग करने से मेगा प्रभिप्राय यह है कि सताधारी पर्टी जो गायन प्रतिनिधियों को जो कि तलेकान में हार जाते हैं उन को पेंशन के रूप में इन में एलेक्ड कर के बैठाल देनी है ग्रोर वह जनता के बीच में काम नहीं करना चाहने हैं, यहीं राजघनी में बैटे-बैने गद्दियों में तेशोप्राराम करना चाहते है, जनना से सनाकं नहीं रव्नना चाहते きै, तो पन एक घन्धा खत्म हो जाय । इमलित मे चाहना है कि विधान परिषनों इप़े ग गज्य सभा को खत्म होना चाहिए। घ्रोर वह् जो पैसा बसे तो जहां देषा के धन्दर कोई

विकास नहीं है. नई रेलवे लाहन नहीं सुली है, सड़के नड्रीं हैं, बिजली नहीं हैं सिचाई का स।घन नहीं है, वह्ँ यह खर्चं किया जाय ताकि वहा भी यह देश की तरक्षी दिग्वने लगे । मभी तक जो बाह्री त्रिदेशी प्रनिनिधि मंडल श्राते हैं उन को राजपथ दिग्वा दिया जाता राष्ट्रपति भवन के ऐशो-श्रागम दिखा दिए जाते हैं. मोगल गार्डेन दिखा दिया जाता है । यदि उन को कहीं देहातों की दशा दिखा दी जाय, पहाड़ी क्षेत्रों की हालत दिव्वा दी जाय जहां कोई उत्यान नहीं हुम्रा वहां के कोल भोल दिग्वा दिए जायें तो वह बानर जा कर इण्डिया की श्रसली तारीफ कर सकते हैं कि इणिडया का fकतना डेवलपमेंट हुपा है । लेकिन विदेशी प्रनिनिधियों को भी धोखे में डाला जाता है। छसलिए जो यह् पैसर बचे हमारा वह देश के उतथान में लगाया जाय घ्रोर यह रायल प्रतिनिfियों को पेंशनर के हूप में न नामिनेट किया जाय। साथ ही जो नामिनेटेड मेम्बर होते है उन को भी खत्म किया जाय।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I want to make it clear that I support this Bill only on the ground that the Punjab Legislature wants it. The Constitution gives the legislature the power to pass a resolution and only on that ground I want to support the Bill. The other discussion regarding the existence or the utility of second chambers is not final nor conclusive. If we want to discuss it and come to a conclusion here, the whole nation has to debate on this.

Side by side, Maharashtra wants expansion of the Upper Chamber; Tamil Nadu wants expansion. So, in this country itself, there are two divergent views.

The legislatures of two important bis States want that it should be maintained and extended, whereas some other States want it to be abolished. It is left to the States. Because the Punjab legislature wants it, therefore I support it and not on the ground that the second chamber is completely useless.

Many things have been said about Rajya Sabha. Suggestions have been made that the Constitution should be amended to

## [Shri Srinibas Misra]

abolish the Rajyd Sabha. For that, the whole Constitution has to go, because about 200 and odd articles have to be amended and thrown out. That is not a matter which can be decided in this debate. So far as this Bill is concerned, because the Punjab Legislature wants it, I support it.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : Sir, I thank the Punjab Government and Assembly for bringing such a progressive legislation. But I am not happy with only West Bengal and Punjab abolishing the sec ond chamber. All the second chambers in the country should be abolished. A second chamb:r is not at all necessary. About the Rajya Sabha, my predecessor said it will be very difficult because the entire Constitution will have to be amended. We will have to surmount every difficulty. Difficulties are there to be overcome. I am obliged no dubt, to the Legislative Council, because I have been a member of the Legislative Counci!. I resigned the nembership of Parliament in order to tide over the constitutional difficulty that was created in the way of my becoming Chief Minister.

We are imitating the foreign countries without rhyme or reason having a second chamber. That is not at all a good sign for the future. I extend my whole-hearted support to this Bill. I hope our Government here also will take credit if they bring a legislation in the next session abolishing the second chamber at the Centre-the Rajya Sabha also, which is a superfluous body.

With these words, I whole-heartedly support the Bill.

भी तुलगां दास जाषव (बारामती): चेपरमेन साहृब, पंजाब अंसेमबली ने क्रवना प्रस्ताव पास षर के वहा की कोन्सिल it बरनास्त करने का जो काम किया है वह एक दषषि से ठीव है। उस मे एक लाभ तो यद होगा कि पंजाब संट का खचं बचेगा, दूसरा लाभ यह होगा कि इस समय बिल को पास करने में जो देगी दोती है, वह बच जएगी ध्रोर तीसरा नाभ यह़ होगा कि जो प्रश्रत्यक्ष इलंबशन ह्रोता है, दूधहायरेकट चुनाव होता है, वह टः जायेंगा, इयोंकि हेमोक्रें। ायरेक्ट

इलैक्शन से आ्राये हुए लोतों के जरिए चले. यही लोकशाही की घ्रार्मा है। ये तीनों फायदे इम में हैं, लेकिन इस के साथ ही साथ जो स्टेट्द् अ्रपने यहां से कौनिमिल को खर्म करने जा रही है उन को कुन्ब खास प्रीकोषान्ज लेने होंगे। खास तोर से जब कींन्सिल खत्म होती है, तो श्रसेम्बनी में जाने के निए भीड़ बढ़ जाती है, उस में लोगों की ज्यादा मारामार होगी तों यदे र्याल रख़ना होगा कि उस के fिये काई ज्गयोरिटी या कोई सीनियोरिटी रखनी चाहिये। ग्रसेम्बली में जब कोई नया श्र:दमी ग्राता है, किसन कभी लंजिसलेचर दे $T$ नहीं है, उस के साथ क्या दिक्कत पेः़ होनी है यहु हम रोजाना देखते हैं। $\dagger$ कोfस्सल जब बग्लास्त होगी तो आ्रसेम्बली में भीड़ बढ़गी, उस के लिये हमें हृर प्रान्त में जो हमारी जिना परिषदें है या ताल्लुका पंचायते हैं, ःन में से ऐसे प्रादमियों को जिन्हें एभसपीरियेन्स्य है, प्रसेम्बली में लेन। चाहियें।

दूसरी बान -- कौनिस्सल में कुछ्ध म्रतपसंख्यकों को नुमाइन्दगी मिलती थी, वह श्रब नही मिलेगी। देका की हालत प्राज यह़ हो रही है कि. जानिवाद घ्रोर सम्पदायवाद बढ़ रहा है: बोट लेने में पैंस का प्रयोग हो रहा है, इसनिये जो घ्रत्पसंख्यक हैं उन का यहा झ्राना मुदिकन हो जायगा-यह बात उन व्रान्तों को जो श्रपन यहां मे कोन्सिल को खत्म करने जा रही हैं, खयाल में रखनी होगी।

तीसरी बात-पसेम्बली के साध जब कीनिस्स होती है, तो बबनों पर दोनों सदनों में विचार होता है, छसमें देर जहरर लभती है, लेकिन काम ठीक होता है। लेकिन जब केवल भ्रसेम्बली रह जायेगी तो यदि ठीक घ्रादमियों को बह्टा पर भेजा जायगा, जो मनुभवी गें, समभदार हों, तब ही काम ठीक होगा।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Mr. Chairman, Sir, while I welcome
this which is going to abolish the Upper House in Punjab, I should like this Bill to include all the States in the country which have Upper House because the purpose for which the Upper Houses were created by the Constitution is net being fulfilled I should say that purpose is being defeated by the way the Upper Houses are functioning in the country. They have become the refuge of those people who cannot face the electorate, those who are dependiog upon the patronage of the political group of the ruling party. In a way they have pinjrapoles in which there are a few docile people, cows, and some stud bulls who go to dominate those Houses. This is happening in our Rajya Sabha also. Therefore, I do not think such an Upper Housc can serve the function of a revising body, or any other function or purpose envisaged for them by the Constitu-tion-makers. So, all the Upper Houses should go. It is more so in the case of the Upper House we have here called Rajya Sabha.

We have here a body called the House of elders so that the rashness of the lower House can be checked. It was supposed that in the lower House some rash people may come, they may pass legislation in a rash manner and the Upper House should check it as a revising chamber. But what is the actual position? Almost all the Young Turks yon find in the Rajya Sabha

## THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI

 SWARAN SINGH): Including your own party?SHRI BAL RAJ MADHOK: I am talking of the ruling party. You are the rulling party now. We follow your example. The way the political patronage is shown in the matter of the Upper House, whether it is done by my party or your party, it is bad and it should be condemned.

Therefore, my suggestion is that not only the Upper Houses in the State should bu abolished but even in the case of the Centre there should be some change. I do not want the abolition of the Upper House altogether in the case of the Centre. But its constitution and composition should be changed. It should take the shape of the American Senate. The American Senatl has two members from each State, as representatives of the State. I would like our Rajya Sabha also to become merely
representative of States. All the States, whether big or small, should have equal representation. If a State is too big and it wants more representation, it can cut itself into two. But as a State it cannot have more representation in the Upper House.

Secondly, some criteria and conditions should $b=$ laid down so that only senior, elderly people with some experience can go there. Now the minimum age limit for becoming a member of the Lok Sabha is $2 j$ and 30 in the case of Rajya Sabha, only a difference of five years which is not a difference at all. Therefore, some other criteria should be laid down for membership of the Upper House.

Then, until the constitution and composition of the Upper House is changed the system of nomination must be abolished.

The nominations were kept in order to see that certain people who are ripe in experience, whose experience will be useful in the Upper House and who would not like to fight elections, should be put there. But what do we find? Even in the case of nominations, not only party politics but also factional politics comes in and people who otherwise have no justification to be there are put there as nominated members. They do not behave as nominated people and as elders. We have seen a very unsavoury spectacle these days. No sooner had the split taken place, some of the nominated members, who till yesterday were maintaining some kind of an independence jumped on to the bandwagon of the Prime Minister and post haste joined the Prime Minister's camp. By doing so not only have they lowered themselves but also the Upper House, all over the country. Therefore, I submit that till a change is made in the Constitution and the composition of the Upper Hocise, this practice of nomination to the Upper House shouid be stopped altogether.

SHRI M. YUNUS SALEEM : Sir, I shall ignore the irrelevant points which have been raised but there was one point taised by an hon. Member, whom I have just now satisfied, that by virtue of clause 4 of this Bill, which says :
'In sub-clause (a) of clause (1) of article 16', the word "Punjab". shall be omitted.'
we have got to have a consequential
[Shdi M. Yunus]
amendment of article 168 of the Constitution also. That doubt expressed by my learned friend just now has been considered as the hon. Speaker rightly pointed out.

Now, a few words regarding rhe views expressed by my hon. friends, Shri Somani and others. There is no doubt that the point is debatable. It cannot be said outright that the Upper Houses are always useless in all circumstances. This is not the occasion to discuss the doctrine of direct and and indirect elecrions and the philosophy of having the Upper Chamber and the Lower Chamber. As I submitted, there are advantages and disadvantages, both.

One of the basic ideas introducing the Upper Chambers, inter alia, was that there may be certain interests in a country who may not get proper representation in the Lower House-may be, the Assembly or the House of the people - and their absence may be felt. In order to complete the process of democracy, such elements, interests or minorities-maybe religious, linguistic, or any other minority-may be provided in the Upper House.

Then, as has been rightly said by Shri Somani, certain elderly persons, scholars, seasoned politicians, engineers, doctors etc., may not like to contest elections directly. They may not have the means or may not like to contest elections, But their presence would improve the standard and quality of debate and their contribution would be very valuable to the deliberations of the House Therefor for such persons the existence of an Upper House was felt essential.

So far as the abolition of the Legislative Council is concerned. as I have submitted, it is within the purview of the State Assembly. If a State Assembly resolves that the Legislative Council of that particular State should be abolished. we shall consider it. But if there are certain States which still want to have it. we cannot force them to do away with their Legislative Councils. If there are States which do not have such Council, and want to have them, we can consider their demand also. But this is not the stage for considering both the aspects of the case.

Regarding the amendment of the Constitution, there are so many difficulties in introducing any simple amandment of the

Constitltion. Therefore to discurs the question of the amending the Constitution for the abolition of the Rajya Sabha and the Councils is a farfetched proposition.

MR. CHAIRMAN : The question is; "That the Bill be passed."

The motion was adopted.
16.25 hrs.

## INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill. Shri, P. C. Scthi.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): On a point of order, Sir. This Bill cannot be moved now Please look at article 117 of the Constitution. Article 117 (1) says:
"A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of artich 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President..."
The recommendation of the President is necessary under article 117 (1) for intioducing or moving the Bill.

Now, in the Bulletin, Part II, No. 1320, the recommendation of the President is as follows :
"The President having been informed of the subject-matter of the proposed Bill further to amend the Internatioual Monetary Fund and Bank Act, 1945 recommends the introduction of the Bill in the Rajya Sabha."
What has he recommended? Only the introduction of the Bill has been recommended by the President. What is the Minister doing now? Hc is moving the $\mathrm{B} \|$ for consideration. He cannot do it now because the recommendation of the President is only for its introduction.

MR. CHAIRMAN : Please read it further.


[^0]:    *SHRI E K. NAYANAR (Palghat) : Mr. Chairman, Sir, utilising the facility that has been provided to us to speak in our own language I would like to speak in Malayalam. It is for the first time that I am getting an opportuni'y to speak in my mother tongue in Parliament. Sir, at this time when this Bill is going to be passed I would like to say with some pride that it was my State which took away the Upper Chamber first. In Kerala, when the Travancore Assembly was constituted there was no Upper Chamber, We are now trying to take away the Upper Chamber from each State and as a part

[^1]:    *The original speech was delivered in Malayalam.

